



बिजली कटौती और मनमाने बिलों के विरोध में एमपीईबी कार्यालय का घेराव



मंदसौर। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती, शहरी उपभोक्ताओं को मनमाने बिल जारी करने और अवैध वसूली की शिकायतों को लेकर सोमवार को जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेस नेता दीपकसिंह गुर्जर के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने एमपीईबी के जिला कार्यालय का घेराव किया। विधायक विपिन जैन भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बिजली व्यवस्था में सुधार, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि रोकने की मांग उठाई। दीपकसिंह गुर्जर ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन का वाचन करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में दिन और रात बिजली

कटौती से आमजन परेशान हैं। उन्होंने त्योहारों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, स्मार्ट मीटर आंदोलन के दौरान दर्ज पुलिस प्रकरण समाप्त करने तथा बिजली चोरी और ओवरलोड के कथित झूठे मामलों को वापस लेने की मांग की। बकाया बिलों के कारण बैंक खाते होल्ड करने और कुर्की जैसी कार्रवाइयों में राहत देने की मांग भी उठाई गई। विधायक विपिन जैन ने कहा कि किसानों को पर्याप्त बिजली मिलना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका निराकरण करने की बात कही। नई डीपी लगाने के नाम पर राशि मांगने की शिकायत प्रदर्शन के दौरान

अधीक्षक यंत्री योगेश आठनरे के समक्ष नई डीपी लगाने के नाम पर पांच हजार रुपये मांगने, बिना रसीद राशि लेने और मनमाने बिजली बिल जारी करने की शिकायतें रखी गईं। विधायक जैन ने एक पीडित उपभोक्ता को मौके पर बुलाकर बिना रसीद राशि लेने का मामला उठाया। प्रदर्शनकारियों ने शिकायतों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की। इससे पहले गांधी चौराहे से रैली निकाली गई, जो सरदार पटेल चौराहा, महाराणा प्रताप बस स्टैंड और महु-नीमच मार्ग होते हुए एमपीईबी कार्यालय पहुंची। इसमें कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। कंपनी का पक्ष = उत्पादन में दिक्कत और बढ़ते लोड से हो रही कटौती मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री योगेश आठनरे ने बताया कि विधायक विपिन जैन और जिला पंचायत सदस्य दीपकसिंह गुर्जर कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती की समस्या केवल मंदसौर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रही है। उत्पादन इकाइयों में आ रही समस्याओं और रात के समय बिजली की मांग बढ़ने से मांग और आपूर्ति के बीच करीब 2800 मेगावाट का अंतर बताया जा रहा है।

वोट चोरी के विरोध में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेसजन, निष्पक्ष चुनाव की उठाई मांग

राहुल गांधी के आह्वान पर मंदसौर में निकला विरोध मार्च, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प देहराया

मंदसौर। वोट चोरी के विरोध और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर सोमवार को कांग्रेस ने मंदसौर में विरोध मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर आयोजित इस मार्च में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। विधायक विपिन जैन के कार्यालय से शुरू हुआ मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के समर्थन में नारे लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग उठाई। विरोध मार्च विधायक कार्यालय से खाना होकर बीपीएल चौराहा, गोल चौराहा और नई आबादी पहुंचा। यहां से मार्च वापस विधायक कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुआ। पूरे मार्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लहराते



हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार की अहमियत और निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर विधायक विपिन जैन ने कहा कि लोकतंत्र में

जनता का वोट सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। मतदान की पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर उठ रहे सवालों का विधायक विपिन जैन ने कहा कि लोकतांत्रिक

संस्थाओं को मजबूत बनाने और संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाती रहेगी। मार्च में पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, मो. हनीफ शेख, विनोद शर्मा, विकास दशोरा, खलील शेख, सुरेंद्र कुमारवत, राजेश सोलंकी, आसिफ छिपा, श्याम गुगर, युजस मेव, आदित्य पाटिल, दिलीप देवड़ा, कमलेश सोनी, शैलेंद्र गोस्वामी और सुदीप पाटिल शामिल रहे। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रफत पर्यामी, इष्टा भाचावत, राखी सत्रावाला, अनीता भदोरिया, सुनीता बंडी, नम्रता सत्रावाला और योगिता बेरगी मौजूद रहीं। विधायक प्रतिनिधियों में तरुण खींची, राजनारायण लाड, सुनील बसेर, संजय नाहर, खलील पटान, अधिपेक पाटीदार, एन.डी. वैष्णव, पंकज जोशी, अंबालाल हिंगोरिया, विश्वास दुबे, राजेश फारम्या, रईस पटवारी, बलवंत सिंह चौहान, कमलेश जैन, मुकेश यादव और सादिक गोरी सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर सख्ती, 50 दिन से लंबित मामलों के निराकरण पर जोर



मंदसौर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों के निराकरण में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। विशेषकर 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निपटया जाए। इसके लिए सभी अधिकारी प्रतिदिन कम से कम एक घंटा निर्धारित कर शिकायतों के निराकरण पर ध्यान दें। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने यह निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ अनुकूल जैन सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में राजस्व विभाग की बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित मिलने पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। सीतामऊ, गरोट और मल्हारागढ़ के तहसीलदारों के यहां अधिक शिकायतें लंबित पाए जाने पर उन्हें अगली बैठक में शिकायतों के निराकरण की जानकारी के साथ स्वयं उपस्थित होने को कहा गया। मंदसौर नगर पालिका में भी करीब 700 शिकायतें लंबित मिलने पर कलेक्टर ने नगरपालिका अधिकारी को कारण

बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। जिले में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने सीतामऊ एसडीएम शिवानी गर्ग द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की। त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलाट रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा राजस्व विभाग को अभियान तेज करने और अधिक से अधिक नमूने लेने के निर्देश दिए। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया। स्वामित्व अभियान की समीक्षा में भानपुरा, आतिथ्य में माँ सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रबंधित तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सराहना की गई। वहाँ मंदसौर, मल्हारागढ़, सीतामऊ और सुवासरा में कार्य की गति बढ़ने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि मंदसौर जिले को प्रदेश में सबसे अधिक लक्ष्य मिला है, ऐसे में प्रयास होना चाहिए कि जिला प्रदर्शन के मामले में भी प्रदेश में अखिल रहे। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत अगला जनसंवाद शिविर 16 अक्टूबर को मल्हारागढ़ विकासखंड के नारायणगढ़ में आयोजित होगा।

जेएच कॉलेज में शिक्षा से विकसित भारतथीम पर विविध शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित

बैतूल। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल में अखिल भारतीय शिक्षा समागम-2026 के अंतर्गत 5 से 10 अक्टूबर तक ‘शिक्षा से विकसित भारत’ थीम पर विभिन्न शैक्षणिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. मोनाक्षी चौबे के मार्गदर्शन में आयोजित इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार, तार्किक चिंतन, तकनीकी जागरूकता, रचनात्मकता तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति

रुचि विकसित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी प्राचार्य डॉ. बी.डी. नागले की अध्यक्षता तथा राजनीति शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. धर्मेन्द्र कुमार एवं इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. पल्लवी दुबे के विशिष्ट आतिथ्य में माँ सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। भावना सूर्यवंशी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। भूमिका वक्तव्य में प्रो. राकेश कुमार पवार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप आयोजित ये गतिविधियाँ विद्यार्थियों को शिक्षा के बदलते स्वरूप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता

के उपयोग तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में शिक्षा की भूमिका समझने का अवसर प्रदान करती हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. बी.डी. नागले ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बताते हुए विद्यार्थियों से ज्ञान, कौशल, नवाचार और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस सदन की राय में शिक्षा में एआई का प्रयोग विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने में सहायक है विषय पर आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता में चुकी है।

विद्यार्थियों ने डिजिटल शिक्षण, शिक्षा की गुणवत्ता, तकनीकी निर्भरता, डिजिटल असमानता तथा शिक्षक-विद्यार्थी संवाद जैसे पहलुओं पर विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता का संयोजन ऋषिकांत पंक्ति ने किया तथा डॉ. विश्वदयाल साहू एवं प्रो. कीर्ति वराटे ने मार्गदर्शन दिया। पक्ष में मयंक साहू प्रथम, आदित्य राठौर द्वितीय एवं लिपिक देशमुख तृतीय रहे, जबकि विपक्ष में योगी देशमुख प्रथम, भावना सूर्यवंशी द्वितीय एवं भूपेंद्र यादव तृतीय स्थान पर रहे।

विज़न इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के छात्र यशराज जाट का राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन



हरदा। विज़न इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, हरदा के लिए यह अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र यशराज जाट, पिता श्री पवन जाट, का हैंडबॉल अंडर-14 बालक वर्ग में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (स्लस्लडू) के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल गेम्स प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। यशराज

जाट ने अपनी प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन एवं खेल के प्रति समर्पण से यह उपलब्धि हासिल कर विद्यालय और हरदा जिले का गौरव बढ़ाया है। उनके इस चयन से विद्यालय परिवार एवं खेल जगत में खुशी का माहौल है। इस उपलब्धि पर विद्यालय के संस्थापक एवं विधायक डॉ. आर. के. दोगने, संस्था के संचालक श्री कुनाल दोगने, प्राचार्य श्री नितेश जैन, हैंडबॉल कोच श्री गौतम विश्वकर्मा तथा समस्त विद्यालय स्टाफ ने यशराज जाट को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। विद्यालय परिवार को विश्वास है कि यशराज जाट राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय एवं हरदा का नाम रोशन करेंगे।

शिक्षा संजीवनी अभियान: शासकीय स्कूलों को डेस्क- बेंच, सीलिंग फैन, टेबल किए भेंट

बैतूल। जिले में शिक्षा संजीवनी अभियान के तहत शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए बेहतर एवं सुविधाजनक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मूलभूत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। अभियान के तहत जनसहभागिता से स्कूलों में डेस्क-बेंच, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, पंखे, प्रकाश व्यवस्था, ई लर्निंग टूल्स, क्रियाशील शौचालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में शासकीय प्राथमिक शाला अर्जुन नगर को गुरुकुल स्कूल हमलापुर की प्राचार्य श्रीमती संगीता श्रीवास्तव के द्वारा 10 नग डेस्क बेंच की गईं। वहीं एकीकृत माध्यमिक शाला डेकय को श्री मनोमरा टॉडलकर सहायक शिक्षक द्वारा एक सीलिंग पंखा भेंट किया। इसके अलावा एकीकृत माध्यमिक शाला बडोरा स्टाफ के द्वारा कक्षा पहली एवं दूसरी के छात्रों को बैठने के लिए टेबल एवं कुर्सी प्रदान की गईं।

सीएमएचओ ने की मातृ-मृत्यु के कारणों की समीक्षा

बैतूल। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव शर्मा ने 12 अक्टूबर को कार्यालय में समस्त बीपीएम की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने निर्देश दिये कि उपस्थिति सार्थक एप पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा समय का विशेष ध्यान रखें और बिना सार्थक उपस्थिति के वेतन आहरित नहीं किया जाए। कार्य में असंतोषजनक पाए जाने वाले कर्मचारियों की वीसी लेकर समीक्षा की जाये। उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे जाने, इसके लिए बोर्डई, बीपीएम, बीसीएम को मोडल अधिकारी नियुक्त कर स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य इंडीकेटरों में सुधार लाया जाये, एनसीडी स्क्रीनिंग में गति लायी जाये, स्क्रीनिंग की रिपोर्ट पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। इस दौरान उन्होंने मातृ-मृत्यु के कारणों की समीक्षा कर निर्देश दिये कि हार्ड रिस्क गर्भवती महिलाओं की समय पूर्व पहचान कर शत- प्रतिशत संस्थागत प्रसव करायें जायें।

शिक्षा संजीवनी अभियान से ऊंचागोहान में छह शाला भवनों का कायाकल्प

बैतूल। शासकीय विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित शिक्षा संजीवनी अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत चिचोली की ग्राम पंचायत ऊंचागोहान में शाला भवनों के कायाकल्प का कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के छह शाला भवनों की मरम्मत एवं आवश्यक सुधार कार्य कर उन्हें विद्यार्थियों के अध्ययन-अध्यापन के अनुकूल बनाया गया है। शिक्षा संजीवनी अभियान के तहत ग्राम पंचायत ऊंचागोहान क्षेत्र में स्थित सभी शाला भवनों का सहायक यंत्री एवं उपयंत्री सहित तकनीकी दल द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भवनों की स्थिति का आकलन कर उनके



जोर्णोंद्वार के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। जनपद पंचायत चिचोली की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सर्व शिक्षा अभियान के तकनीकी दल के मार्गदर्शन में आवश्यक मरम्मत कार्य कराए गए। मरम्मत एवं रंगाई-पुताई से संवरे विद्यालय भवन ग्राम पंचायत ऊंचागोहान के अंतर्गत कुल छह शालाएं संचालित हैं, जिनमें चार प्राथमिक शाला एवं दो माध्यमिक शाला भवन शामिल हैं। इन शाला भवनों में आवश्यकतानुसार प्लास्टर, पट्टी, वाटरपूफिंग, ऑयल पेंट, टाइल्स लगाने तथा छिड़की, दरवाजे और शटर गेट बदलने जैसे कार्य कराए गए। साथ ही भवनों की रंगाई-पुताई एवं अन्य जरूरी सुधार कार्यों के माध्यम से विद्यालयों को व्यवस्थित और अध्ययन-अध्यापन के लिए अनुकूल बनाया गया है। शाला भवनों की मरम्मत के साथ ही विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी पहल की गई। ग्राम पंचायत के शासकीय कर्मचारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राथमिक शालाओं में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क-बेंच की व्यवस्था की जाएगी। सरपंच एवं ग्राम पंचायत सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारियों ने इस कार्य में सहयोग करने का संकल्प लिया। इस दिशा के परिणामस्वरूप प्राथमिक शाला धौल एवं प्राथमिक शाला कड़वाढाना के विद्यार्थियों के लिए जनसहयोग से डेस्क-बेंच उपलब्ध कराई गईं।

शासकीय पॉलीटेक्निक हरदा में गूलकार्ड एआई सॉल्यूशंस का कैंपस ड्राइव आयोजित

कंप्यूटर साइंस के अंतिम वर्ष के छात्रों ने लिया भाग, दशहरा बाद होंगे साक्षात्कार

हरदा। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने एवं उनकी व्यावसायिक दक्षता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोमवार को शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, हरदा में गूलकार्ड एआई सॉल्यूशंस कंपनी द्वारा कैंपस ड्राइव आयोजित किया गया। महाविद्यालय के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी श्री विकास भुपरकर ने बताया कि कैंपस ड्राइव में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने सहभागिता की। इस दौरान कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा

विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें कंपनी की चयन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि इच्छुक विद्यार्थियों का साक्षात्कार सेंट्रल जंयोजन किया गया तथा आगामी चयन प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। कंपनी प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि पंजीकृत विद्यार्थियों के साक्षात्कार दशहरा पूर्व के पश्चात आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंधन ने कहा कि इस प्रकार के कैंपस ड्राइव विद्यार्थियों को उद्योग जगत से परिचित कराने, उनकी रोजगारपरक क्षमताओं को विकसित करने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

छोटा विज्ञापन
बड़ा लाभ
छोटा विज्ञापन
बड़ा लाभ

वलासीफाई विज्ञापन दरें
150/- रुपये प्रतिदिन 25 शब्दों तक
स्कीम
2 दिन के विज्ञापन पर 2 दिन अतिरिक्त प्रकाशन
5 दिन के विज्ञापन पर 10 दिन अतिरिक्त प्रकाशन
10 दिन के प्रकाशन पर 20 दिन अतिरिक्त प्रकाशन
राष्ट्रीय गरिमा समाचार पत्र में विज्ञापन देकर अपने व्यापार को दें नई उड़ान
सम्पर्क करें : 8602000710, 8602000703
मात्र 1500/- रुपये में पूरे एक माह चलायें

विसंगतियां के बाद 55,000 करोड़ की संपत्ति के सौदे जांच के दायरे में

गुरुग्राम। गुरुग्राम के बाटूआसपुर तहसील में आरकर विभाग के सर्वेक्षण में करीब 25,000 संपत्तियों के रिकॉर्ड में विसंगतियां पाए जाने के बाद 55,000 करोड़ रुपए के सौदे जांच के दायरे में आ गए हैं। इनमें सिलेरे दो सालों में जमीन की कई अनिश्चितियों ने एक ही पैम नंबर के इस्तेमाल की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों में अधिकारी ने बताया कि गौरी गुरुव वाले संपत्ति सौदों में विसंगतियों की जांच के लिए आरकर विभाग, पंडीगढ़ के निदेशक ने सात सदस्यीय टीम का गठन किया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 6 किये शुरू

नई दिल्ली। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6 चला रहा है जिसका उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और सरकारी कार्यालयों में लैबित माननी को कम करना है। यह अभियान विभाग के संबद्ध एवं अखिलस्थ कार्यालयों, केंद्रीय सरकारी अस्पतालों, स्वागत विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संबद्ध संस्थानों में लागू किया जा रहा है।

गिर के बाद अब गुजरात का बरडा बना एशियाई शेरों का नया घर

17 शेरों के लिए अनुकूल आवास, पर्याप्त शिकार और सुरक्षित पर्यावरण की पुष्टि

अहमदाबाद। एशियाई शेर विश्व में केवल गिर के जंगल में ही पाए जाते हैं। हालाँकि, शेर अपने परंपरागत क्षेत्र से बाहर भी विस्तार कर रहे हैं। ऐसे समय में, बरडा का जंगल एशियाई शेरों के लिए एक नया 'घर' बना है। पोरबंदर तथा देवभूमि द्वारका जिलों में फैले बरडा के जंगल की चट्टानी पहाड़ियाँ शेरों को रास आ गई हैं। हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, बरडा वन्यजीव अभयारण्य शेरों के दीर्घकालिक महत्वपूर्ण आश्रयस्थल के रूप में विकसित हो सकता है। सौराष्ट्र में स्थित बरडा वन्यजीव



अभयारण्य 192.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसका बड़ा हिस्सा पोरबंदर तथा देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। यह अभयारण्य वनस्पतियों की असाधारण विविधता से समृद्ध है

और यहाँ कई प्रकार की औषधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें पर्यावरणीय एवं संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियाँ भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने वन्यजीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के प्रयासों को और गति दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गिर के शेरों के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा बरडा के जंगल में रहने वाले पशुपालकों के लिए एक पुनर्वास योजना घोषित की गई है और बरडा का जंगल शेरों के लिए एक सुरक्षित नया घर बना है। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार, बरडा के जंगल में शेरों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आवश्यक आवास, पर्याप्त शिकार और अनुकूल

पर्यावरणीय परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। गिर से परे-बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए एक संभावित गढ़ के रूप में शीर्षक वाला यह अध्ययन पीएलओएस वन में प्रकाशित हुआ है। गुजरात वन विभाग के मोहन राम (आईएफएस), आराधना साहू (आईएफएस), नित्यानंद श्रीवास्तव (आईएफएस),रोहित चौधरी,लहर झाला और यशपाल झाला तथा बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया था। इस अध्ययन में लगभग 144 वर्षों के अंतराल के बाद बरडा के जंगल में फिर से लौटे शेरों के क्षेत्र के उपयोग,आवास के चयन एवं आहार का अध्ययन किया गया। लगभग 144 वर्षों के बाद शेरों ने प्राकृतिक रूप से बरडा में फिर

से अपना ठिकाना बनाया। शुरुआत में एक नर शेर यहाँ आया था और उसके बाद गुजरात वन विभाग द्वारा पाँच मादा शेरों को यहाँ लाया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोदवाडिया ने कहा,एशियाई शेरों के संरक्षण की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण शोध है। अब शेरों की आबादी केवल गिर के जंगल तक सीमित नहीं रही है। गिर के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र से बिखरकर आने वाले शेरों के लिए बरडा का जंगल दूसरा घर बना है। इस वैज्ञानिक अध्ययन के निष्कर्ष इसी का परिणाम हैं। अर्जुन मोदवाडिया ने आगे कहा,मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन ने राज्य सरकार गुजरात में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और शेरों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

मुंबई में 18 से 20 दिसंबर तक होगा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का बड़ा आयोजन

आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत करेंगे उद्घाटन सत्र को संबोधित

मुंबई। विश्वभर के हिंदू नेतृत्व का प्रमुख वैश्विक समागम वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस (डब्ल्यूएचसी) इस बार मुंबई में आयोजित होगा। तीन दिवसीय सम्मेलन 18 से 20 दिसंबर तक बांदा-कुला कॉम्प्लेक्स स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत संबोधित करेंगे। आयोजकों के अनुसार, इसमें 60 से अधिक देशों के 4,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। सम्मेलन में हिंदू नेता, विचारक, उद्यमी, शिक्षाविद्, मीडिया प्रतिनिधि, पेशेवर और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व एक मंच पर जुटेंगे। तीन दिनों के दौरान 45 से अधिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 150 से अधिक वक्ता अर्थव्यवस्था, शिक्षा, मीडिया, राजनीति, महिला सशक्तीकरण,युवा और हिंदू संगठनों सहित विभिन्न विषयों पर विचार रखेंगे।



वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2026 की थीम 'समान ब्रतं सह चितम्' झु साझा प्रतिबद्धता,सामूहिक संकल्प' रखी गई है। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हिंदू समुदाय के विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच संवाद,सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के प्रवर्तक स्वामी विज्ञानानंद ने कहा कि विश्वभर में हिंदू समाज की दृश्यता और प्रतिष्ठा बढ़ी है, लेकिन यह रुकने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा, अकादमिक जगत,

आध्यात्मिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें धर्म की विविध परंपराओं, उनकी समकालीन प्रासंगिकता और विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच संवाद पर चर्चा होगी। समाज प्लेनरी में सामाजिक समरसता, सामुदायिक विकास और हिंदू समाज के सामने मौजूद चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसमें विभिन्न समुदायों, परंपराओं और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भाषा प्लेनरी का उद्देश्य हिंदू समाज की भाषाई विविधता, साहित्य, सभ्यतागत ज्ञान और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण में विभिन्न भाषाओं की भूमिका को रेखांकित करना है। विश्वकर्मा प्लेनरी में कौशल विकास, उद्यमिता, नवाचार और आर्थिक-सामाजिक विकास में कारीगरों, शिल्पकारों तथा पेशेवरों के योगदान पर चर्चा होगी। इसके माध्यम से कुशल कार्य की गरिमा बढ़ाने और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने के उपायों पर भी मंथन किया जाएगा। इस वर्ष वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के साथ पहली बार वर्ल्ड हिंदू एक्सपोज़ का भी आयोजन किया जाएगा।

सम्मान और स्वावलंबन से ही साकार होगा विकसित यूपी का सपना : सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र पर दिया मातृशक्ति की सुरक्षा का संदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचरिनी देवी से मंगलकामना करने के साथ प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां दुर्गा की महिमासुर पर विजय धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अहंकार, दुराग्रह, आसक्ति और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विनम्रता, साहस, शक्ति, संकल्प, न्याय और धर्म की विजय का भाव मां दुर्गा के नौ स्वरूपों में निहित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति को सुरक्षित,सम्मानित और आत्मनिर्भर बनाना इसी चेतना का आधार है। उन्होंने प्रदेशवासियों से नवरात्र पर महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा और महिला स्वावलंबन के लिए योगदान देने का संकल्प लेने की अपील की।



'योगी की पाती' में मुख्यमंत्री ने लिखा कि जब महिमासुर के अत्याचार से तीनों लोकों में त्राहि-त्राहि मच गई, नव देवताओं की सामूहिक ऊर्जा से एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ, जो साक्षात् आदिशक्ति थीं। मां दुर्गा ने महिमासुर का वध कर धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना की। उन्होंने कहा कि महिमासुरमर्दिनी की इसी विजय और शक्ति की आराधना के पावन पर्व शारदीय नवरात्र पर वह प्रदेशवासियों को हृदय से मंगलकामनाएं देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि

लंका विजय से पूर्व प्रभु श्रीराम ने मां जगतजननी को साधना की थी। साधना के लिए 108 नीलकमलों में एक कम पड़ने पर उन्होंने अपना नयन ही अर्पित करने का निश्चय किया। तब मां प्रकट हुईं और उन्हें विजय का वर दिया। उन्होंने कहा कि ममता और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति मां त्रैलोक्य की रक्षा के लिए चंडी का रूप धारण करती हैं और मधु-कैटभ, शुंभ-निशुंभ तथा रक्तबीज जैसे दानवों का संहार करती हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहंकार, दुराग्रह,आसक्ति और बढ़ती नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विनम्रता,साहस, शक्ति,संकल्प,न्याय और धर्म की विजय का भाव ही मां के नौ स्वरूपों में निहित है। उन्होंने कहा कि आज भी जब समाज ऐसी प्रवृत्तियों से संघर्ष करता है,तब नवरात्र हमें याद दिलाता है कि सच्जनता तभी प्रभावी होती है, जब उसमें शक्ति और संकल्प का सामर्थ्य हो।

ओडिशा छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़ी बढ़त



60 महाविद्यालयों में हुए चुनाव में 252 पदों पर अभाविप की निर्विरोध जीत

भुवनेश्वर। ओडिशा में छात्रसंघ चुनावों से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के प्रत्याशियों ने 60 महाविद्यालयों में 252 पदों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है। संगठन के अनुसार, इनमें 12 अध्यक्ष, 17 महासचिव, 22 उपाध्यक्ष और 23 संयुक्त सचिव समेत विभिन्न पद शामिल हैं। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद इन पदों पर अभाविप के प्रत्याशियों के सामने कोई अन्य उम्मीदवार नहीं बचा। अभाविप ने इस सफलता को विद्यार्थियों के बीच संगठन की सक्रियता और समर्थन का परिणाम

अभाविप ने क्लीन स्वीप किया है। दिल्ली, पंजाब,केरल और असम सहित देश के विभिन्न राज्यों में छात्रसंघ चुनावों में अभाविप को मिली सफलता भी विद्यार्थियों के बीच संगठन की बढ़ती स्वीकार्यता की दर्शाती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री श्रवण बी. राज ने कहा,ओडिशा में अभाविप की लड़ाई कांग्रेस और बीजू जनता दल की उस राजनीतिक कार्यशैली से है, जिसमें विद्यार्थी हितों की अपेक्षा राजनीतिक समीकरणों को प्राथमिकता दी जाती है। एनएसयूआई और बीसीजेडी को मिलने वाले राजनीतिक समर्थन के बावजूद कई महाविद्यालयों में प्रत्याशियों का अभाव यह दर्शाता है कि छात्र राजनीति में केवल राजनीतिक प्रभुभूमि या समर्थन पर्याप्त नहीं है; विद्यार्थियों के बीच निरंतर काम करना और उनका विश्वास अर्जित करना आवश्यक है। अभाविप का कार्यकर्ता वर्षभर विद्यार्थियों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझता है और उनके समाधान के लिए निरंतर संघर्ष करता है, जबकि कुछ संगठन केवल चुनाव के समय सक्रिय दिखाई देते हैं।

बुलेट ट्रेन परियोजना में रेलमार्ग के ऊपर सभी पोर्टल बीम का निर्माण पूरा

बड़ोदरा। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत गुजरात के वडोदरा में दिल्ली-मुंबई राजधानी रेलमार्ग के ऊपर सभी 14 पोर्टल बीम का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इससे इस व्यस्त रेलमार्ग के ऊपर 40 मीटर लंबे कंपोजिट गर्डर स्थापित करने और बुलेट ट्रेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) के अनुसार, वडोदरा में यह उपलब्धि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मौजूदा रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस खंड में बुलेट ट्रेन का मार्ग चालू रेल लाइनों और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिससे निर्माण कार्य तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। वडोदरा में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का संबंधित हिस्सा लगभग 8.3 किलोमीटर लंबा है। इस खंड में भारतीय रेलवे की पांच रेल लाइनें आती हैं, जिनमें दो मुख्य लाइनें शामिल हैं। बुलेट ट्रेन का मार्ग दिल्ली-मुंबई राजधानी मुख्य रेलमार्ग को तिरछे पार करता है, जिसके कारण विशेष संरचनाओं का निर्माण करना पड़ा है।

BURGO CONSTRUCTION

WHERE QUALITY MEETS INNOVATION

- CONSTRUCTION
- RENOVATION
- DESIGNING
- CONSULTATION
- PLANNING
- MANAGEMENT

CALL NOW

+91-860-2000-710

WWW.BURGOCONSTRUCTION.COM



सम्पादकीय

आम इनसान की सेहत के साथ खिलवाड़

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर धतूरे जैसे प्रतिबंधित बीज, और भ्रामक दावों वाले खाद्य पदार्थ खुलेआम बिक रहे हों, तो उसे सीधे तौर पर आम इनसान की सेहत के साथ खिलवाड़ ही समझा जा सकता है। अमेजन, स्विजी, इंस्टामार्ट, बिग-बास्केट आदि जैसी दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) की कार्रवाई को एक अति-आवश्यक कदम माना जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर धतूरे जैसे प्रतिबंधित बीज, और भ्रामक दावों वाले खाद्य पदार्थ खुलेआम बिक रहे हों, तो उसे सीधे तौर पर आम इनसान की सेहत के साथ खिलवाड़ ही समझा जा सकता है। डिलिवरी ऐप्स की संचालक कंपनियों को कोई समाज ऐसा आम जोखिम पैदा करने की इजाजत नहीं दे सकता। दरअसल, ये पूरा प्रकरण क्रिक-कॉमर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों की गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी खामियों को उजागर करता है। या यह भी कहा जा सकता है कि यह नियम-कानूनों के प्रति इन कंपनियों की लापरवाही की ठोस मिसाल है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियां अक्सर तर्क देती हैं कि वे सिर्फ ‘इंटरमीडिएटरी’ यानी विक्रेता एवं ग्राहक के बीच खरीद-बिक्री का माध्यम हैं। लेकिन, गौरतलब है कि ये कंपनियां धुआंधार विज्ञापनों से अपना ब्रांड मूल्य बनाती हैं, जिसका आधार खरीदारों का भरोसा है। इसलिए किसी ऐप पर हानिकारक पदार्थ बिकें, तो उसकी जवाबदेही प्लेटफॉर्म संचालक कंपनी की भी बनती है। अतः यह अनिवार्य हो गया है कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता, उस पर लिखे दावों और अपनाए गए सुरक्षा मानकों के बारे में ऐप संचालक कंपनियों को भी जवाबदेह बनाया जाए। भ्रामक मार्केटिंग के जरिए कथित स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री का चलन हाल में काफी बढ़ा है। उपभोक्ताओं में सेहत के प्रति नई आई संवेदनशीलता का गलत फायदा अनेक कंपनियां उठा रही हैं। इसीलिए इसे रोकना अनिवार्य हो गया है। एफएसएसआई ने अपने ताजा कदम से यह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रामक दावों के जरिए हानिकारक पदार्थों की मार्केटिंग दंडनीय अपराध है। बहरहाल, यह कार्रवाई महज एक शुरुआत है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के तेज गति से हुए प्रसार के मद्देनजर महज बिक्री रोकना या प्रतीकात्मक जुर्माना लगाना पर्याप्त नहीं होगा। बल्कि इसके लिए सख्त कानूनी प्रावधान लागू किए जाने चाहिए, ताकि ई-कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता सुरक्षा से कोई समझौता न हो। फिलहाल, एफएफएसआई ने ऐसी शुरुआत की है, जिसे आगे ले जाने का दायित्व सरकार और संसद पर है।

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के नए क्षितिज और बदलती तस्वीर

विष्णु प्रसाद वर्मा

छत्तीसगढ़ की पावन धरा आज न केवल अपने प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जा रही है, बल्कि यह राज्य शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई अभूतपूर्व क्रांति का साक्षी बन रहा है। राज्य में उच्च शिक्षा अब केवल पारंपरिक ज्ञान अर्जन का माध्यम मात्र नहीं रह गई है, बल्कि यह प्रदेश के लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का एक सशक्त एवं टिकाऊ आधार बन चुकी है। राज्य सरकार ने ‘सेवा का संकल्प’ और ‘सेवा आपके द्वार’ के मूलमंत्र को धरातल पर उतारते हुए शिक्षा के मंदिर को हर उस गांव और सुदूर अंचल तक पहुंचाया है, जहाँ कभी उच्च शिक्षा पाना एक कठिन स्वप्न जैसा था। इस दूरदर्शी और संवेदनशील सोच का ही सुखद परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश का उच्च शिक्षा परिदृश्य एक नई चेतना और %सेवा कहानी की% का नया स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है। वर्षों से चले आ रहे क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने विशेष प्राथमिकता के साथ वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की है। केवल नए कॉलेज खोलना ही ध्येय नहीं रहा, बल्कि पहले से संचालित संस्थानों में नए संकायों, नवीन विषयों और अध्ययन सीटों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है ताकि किसी भी मेधावी छात्र को अवसरों की कमी न महसूस हो। इसके साथ ही, उच्च शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढाँचे को एक नया और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है।

छत्तीसगढ़ की पावन धरा आज न केवल अपने प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जा रही है, बल्कि यह राज्य शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई अभूतपूर्व क्रांति का साक्षी बन रहा है। राज्य में उच्च शिक्षा अब केवल पारंपरिक ज्ञान अर्जन का माध्यम मात्र नहीं रह गई है, बल्कि यह प्रदेश के लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का एक सशक्त एवं टिकाऊ आधार बन चुकी है। राज्य सरकार ने ‘सेवा का संकल्प’ और ‘सेवा आपके द्वार’ के मूलमंत्र को धरातल पर उतारते हुए शिक्षा के मंदिर को हर उस गांव और सुदूर अंचल तक पहुंचाया है, जहाँ कभी उच्च शिक्षा पाना एक कठिन स्वप्न जैसा था। इस दूरदर्शी और संवेदनशील सोच का ही सुखद परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश का उच्च शिक्षा परिदृश्य एक नई चेतना और %सेवा कहानी की% का नया स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है। वर्षों से चले आ रहे क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने विशेष प्राथमिकता के साथ वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की है। केवल नए कॉलेज खोलना ही ध्येय नहीं रहा, बल्कि पहले से संचालित संस्थानों में नए संकायों, नवीन विषयों और अध्ययन सीटों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है ताकि किसी भी मेधावी छात्र को अवसरों की कमी न महसूस हो। इसके साथ ही, उच्च शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढाँचे को एक नया और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है।

छत्तीसगढ़ की पावन धरा आज न केवल अपने प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जा रही है, बल्कि यह राज्य शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई अभूतपूर्व क्रांति का साक्षी बन रहा है। राज्य में उच्च शिक्षा अब केवल पारंपरिक ज्ञान अर्जन का माध्यम मात्र नहीं रह गई है, बल्कि यह प्रदेश के लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का एक सशक्त एवं टिकाऊ आधार बन चुकी है। राज्य सरकार ने ‘सेवा का संकल्प’ और ‘सेवा आपके द्वार’ के मूलमंत्र को धरातल पर उतारते हुए शिक्षा के मंदिर को हर उस गांव और सुदूर अंचल तक पहुंचाया है, जहाँ कभी उच्च शिक्षा पाना एक कठिन स्वप्न जैसा था। इस दूरदर्शी और संवेदनशील सोच का ही सुखद परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश का उच्च शिक्षा परिदृश्य एक नई चेतना और %सेवा कहानी की% का नया स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है। वर्षों से चले आ रहे क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने विशेष प्राथमिकता के साथ वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की है। केवल नए कॉलेज खोलना ही ध्येय नहीं रहा, बल्कि पहले से संचालित संस्थानों में नए संकायों, नवीन विषयों और अध्ययन सीटों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है ताकि किसी भी मेधावी छात्र को अवसरों की कमी न महसूस हो। इसके साथ ही, उच्च शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढाँचे को एक नया और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है। पुराने जीर्ण-शीर्ण भवनों का कार्याकल्प करने के साथ-साथ आधुनिक वास्तुकला से युक्त नए परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक ज्ञान से जोड़ने के लिए उन्नत प्रयोगशालाएँ, समृद्ध ज्ञानकोश से युक्त पुस्तकालय और अत्याधुनिक ई-क्लासरूम जैसी डिजिटल सुविधाएँ परिसरों में स्थापित



की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण छात्र भी सीधे वैश्विक ज्ञान नेटवर्क से जुड़ पा रहे हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता को वैश्विक मानकों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का चरणबद्ध और सुनियोजित क्रियान्वयन किया जा रहा है। जुलाई 2024 से सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में इसे सफलतापूर्वक लागू करने के बाद, अब वर्ष 2025 से पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर और इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी एनईपी लागू कर दिया गया है। इसी विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सत्र 2025-26 से चार वर्षीय बी.एड., प्राच्य संस्कृत और बीपीएड जैसे व्यावसायिक तथा विशिष्ट पाठ्यक्रमों को भी इसके दूरदर्शी दायरे में लाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को बहुविषयक और व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त हो सके। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और जीवन कौशल का विकास है। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, परीक्षा के तनाव और भविष्य की चिंताओं को दूर करने के लिए महाविद्यालयों में करियर एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ विशेषज्ञों और

मनोवैज्ञानिकों द्वारा निरंतर काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, शिक्षक-छात्र के आदर्श अनुपात को बनाए रखने के लिए नए पदों का सृजन किया जा रहा है और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के माध्यम से %नैक% मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अकादमिक कैलेंडर में खेलकूद, एन.एस.एस., एन.सी.सी. व योग जैसी गतिविधियों के समावेश से युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का बीजारोपण हो रहा है। राज्य शासन की ये बहुआयामी और दूरदर्शी नीतियाँ बुनियादी ढाँचे, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों को एक साथ जोड़कर युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रांतिकारी प्रावधानों, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर और समर्पित नेतृत्व के बल पर छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा क्षेत्र आज अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका है। %सेवा संकल्प अभियान% के तहत उठाए गए ये ऐतिहासिक कदम न केवल वर्तमान पीढ़ी को संवार रहे हैं, बल्कि आने वाले कल के लिए ऐसे समर्थ, सजग और हुनरमंद नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं जो वैश्विक मंच पर छत्तीसगढ़ और भारत का नाम गर्व से रोशन करेंगे। लेखक सहायक संचालक हैं।

इसलिए सीईसी को हटा पाना है मुश्किल

अभिषेक शुक्ल

पिछले दो दिन 10 और 11 अक्टूबर कॉंकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और अन्य के प्रदर्शन से दिल्ली के कुछ हिस्सों में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त रहे। भारत निर्वाचन आयोग के भीतर असहमति की रिपोर्टों, विपक्षी दलों के प्रदर्शन और उच्चतम न्यायालय में दाखिल नई याचिकाओं ने एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की शक्तियों, जवाबदेही और उनके पद की सुरक्षा पर राष्ट्रीय विमर्श छेड़ दिया है। इन विरोध प्रदर्शनों और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच एक अहम संवैधानिक सवाल खड़ा होता है, क्या सार्वजनिक प्रदर्शन या राजनैतिक दबाव के आधार पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया या निलंबित किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर राजनीतिक बयानों में नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के प्रावधानों और निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वायत्तता में निहित है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति करते हैं। वर्ष 2022 तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर संसद ने कोई कानून नहीं बनाया था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को सलाह पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते रहे हैं। किन्तु वर्ष 2023 में उच्चतम न्यायालय ने %अनुप बरनवाल% वाद में निर्देश दिया कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती, तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान (मुख्य) न्यायाधीश सदस्य होंगे। इसी वर्ष 2023 में संसद ने एक अधिनियम पारित कर देश के प्रधान न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर कर दिया और उनके स्थान पर प्रधानमंत्री नामित एक कैबिनेट मंत्री को सदस्य बनाया गया। यह बदलाव भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे और शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को मजबूत करता है। भारत के प्रधान न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त की चयन समिति का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि न्यायपालिका का प्रमुख कार्यपालिका की नियुक्तियों में सक्रिय भूमिका निभाता है तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण का सिद्धांत कमजोर होता है। इसके पीछे एक दूसरा तर्क यह है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विवाद भविष्य में न्यायपालिका के सम्मुख आ सकते हैं। ऐसे में जब न्यायपालिका का प्रमुख उस नियुक्ति प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार रहा हो तो न्यायालय के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का निष्पक्ष न्यायिक पुनरावलोकन एक चुनौती बन जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क यह है कि यदि भारत के प्रधान न्यायाधीश को संविधान संहिता में शामिल हो जाएगी। वैसे भी, उच्च संवैधानिक पदों की नियुक्तियों में सरकार की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। यही सामान्य सार्वभौमिक नियम है। इससे सरकार और उच्च संवैधानिक पदों के मध्य गतिरोध की संभावना कम होती है और सहयोग बढ़ता है। सरकार की जवाबदेही तय करना आसान हो जाता है क्योंकि सरकार अपनी



असफलता के लिए उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों को दोष नहीं दे सकती। उदाहरण के लिए, विपक्ष के संवैधानिक संस्थाओं के साथ असहयोग और विरोध प्रकट करने से कोई संवैधानिक संकट पैदा नहीं होता। किन्तु यदि सरकार और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के मध्य असहयोग और टकराव पैदा हो गया तो यह एक संवैधानिक संकट को जन्म दे सकता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया था। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को लेकर उच्चतम न्यायालय में डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिकॉर्म्स की याचिकाएं लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नए कानून ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को समिति से हटाकर उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया है। इससे समिति में सरकार को 2-1 का स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, जो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अभी सितंबर 2026 में उच्चतम न्यायालय की दो जजों की बेंच ने इस मामले में खंडित फैसला सुनाया। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने इस मामले को अंतिम फैसले के लिए एक बड़ी संविधान पीठ को सौंप दिया है। इस घटनाक्रम में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब %इंडियन एक्सप्रेस% में 23 सितंबर 2026 को छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 10 महीने में चुनाव आयोग के दो सदस्यों ने आयोग के निर्णयों पर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। इनमें फॉर्म 6 में किए गए बदलाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इस रिपोर्ट की आधार बनाकर अधिवक्ता शैलेंद्र (शलभ) मणि त्रिपाठी और सह-याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली को

चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों को दरकिनार करते हुए मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित एकतरफा निर्णय लिए हैं। यह 2023 के अधिनियम की धारा 18 का सीधा उल्लंघन है, जो यह अनिवार्य करती है कि चुनाव आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लिए जाने चाहिए। राकेश कुमार सिंह की याचिका में जहां मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल निलंबित करने की मांग की गई, वहीं त्रिपाठी की याचिका में मांग की गई कि बिना सामूहिक अधिकार के मतदाता सूची में बदलाव करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाए। यद्यपि न्यायालय ने तत्काल निलंबन से इनकार कर दिया लेकिन चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि जांच में यह साबित होता है कि फैसले बिना बहुमत के लिए गए तो उन फैसलों को रद्द कर दिया जाएगा। इस तथ्य को परखने के लिए अदालत ने चुनाव आयोग की आंतरिक फाइलों, बैठकों के एजेंडों और कार्यवृत्त को न्यायिक समीक्षा के लिए तलब किया है। किन्तु यहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त को निलंबित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें केवल उन्हें पद से हटाने की एक अत्यंत कठोर प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 324(5) के तहत, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और आधार यथा %साबित कजाकर या असमर्थता% पर ही हटाया जा सकता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। संविधान में निलंबन तंत्र की यह अनुपस्थिति चुनाव

आयोग की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए एक जानबूझकर बनाया गया सुरक्षा कवच है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका अनुशासनात्मक कार्रवाई के बहाने मुख्य चुनाव आयुक्त को मनमाने ढंग से किनारे न कर सके और चुनाव आयोग के स्वतंत्र कामकाज को अस्थायी रूप से बाधित या प्रभावित न कर पाए। ऐसे में न्यायालय से मुख्य चुनाव आयुक्त के निलंबन की मांग करना न्यायसंगत नहीं है। दूसरी ओर, मुख्य चुनाव आयुक्त को 2023 के अधिनियम की धारा 16 के तहत मुकदमे के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी भी कार्य या लिए गए निर्णय के खिलाफ कोई भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती और यह सुरक्षा उनके पद छोड़ने के बाद भी बरकरार रहती है। जब तक 2023 के अधिनियम की धारा 16 को न्यायालय द्वारा विधिशून्य नहीं घोषित किया जाता, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में उच्चतम न्यायालय 2023 के अधिनियम के प्रावधानों और भारत निर्वाचन आयोग के निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन कर उसे विधिशून्य घोषित कर सकता है। किन्तु उच्चतम न्यायालय न तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति के सदस्यों का निर्धारण कर सकता है और न ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा या निलंबित कर सकता है। नियुक्ति और बर्खास्तगी कार्यपालिका का क्षेत्राधिकार है। इसमें न्यायपालिका का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। इसी बीच विपक्ष के सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। किन्तु यहां पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यपालिका राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त नहीं है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल तभी हटा सकते हैं जब संसद के दोनों सदन उन्हें विशेष बहुमत द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत करें। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 (5) में दी गई है। इसके लिए विपक्ष को सदन में प्रस्ताव लाना होगा। किन्तु विपक्ष के पास इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता इस बात में निहित है कि वे राजनीतिक दबावों और सार्वजनिक बहसों से अप्रभावित रहकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें। संविधान निर्माताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पद को कार्यपालिका की मनमर्जी और तात्कालिक राजनीतिक उथल-पुथल से परे रखने के लिए ही महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया की ढाल दी। वर्तमान विवाद यह स्पष्ट करता है कि निर्वाचन आयोग के आंतरिक प्रशासनिक निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा की नजर भले ही बनी रहे लेकिन राजनीतिक मांग या अदालती अर्जी के सहारे मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना या निलंबित करना न तो संवैधानिक रूप से संभव है और न ही संसदीय अंकगणित के लिहाज से आसान। अंततः, संस्था की गरिमा और संवैधानिक सीमाओं का संतुलन ही भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है। (लेखक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

राशिफल

मेष राशि : आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास मजबूत बनेगा। आप काम को बेहतर तरीके से करने में सक्षम होंगे। आज आपको व्यापार में लाभ होगा लेकिन आप साझेदारी में थोड़ी सतर्कता बनाये रखें। आज आपका दायित्व जीवन सुहावल रहेगा और आपको किसी काम में जीवनसाथी का साथ मिलेगा जिससे काम आसानी से हो जायेगा।
वृष राशि : आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज कारोबार में आपको बढ़िया धन लाभ होगा। साथ ही आपके व्यावसायिक रिश्ते भी सुधरेगे। आज प्रायदेर लोकरी में कार्यरत व्यक्तियों को पदेनक्ति के अवसर प्राप्त होंगे। आज किसी व्यक्ति से चल रही अनबन खत्म होगी, आपसी मधुरता बढ़ेगी।
मिथुन राशि : आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। आज आप कुछ ऐसा करेंगे, जिससे आपके पड़ोसी भी आपकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पायेंगे। यदि आज आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो दिन अच्छा है आप खरीद सकते हैं।
कर्क राशि : आज का दिन आपके लिए सुहावाल रहेगा। आज आप निजी जीवन में चल रही समस्याओं को सुलझा लेंगे, आपका मन संतुष्ट होगा। आज कुछ भी करने से पहले आज आपने बड़ों से परा अवस्था लें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आज नवविवाहिता दंपति अत्यात्मिक यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं।
सिंह राशि : आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आज आप नयी योजनाओं की शुरुआत करके भविष्य में बड़ा धन लाभ कमायेंगे। आज आप वो कामयाबी पाने में सफल रहेंगे, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी। यदि आपके कानूनी मामले कोर्ट-कचहरी में चल रहे तो आज आपको उनसे राहत मिलेगी।
कन्या राशि : आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज आप बड़े भाई की मदद से अपना काम कमप्लीट करने में सफल रहेंगे। आज आपकी खोई हुई चीज वापस मिलने से आपको बहुत खुशी होगी। आज बिजनेस में आपकी दृष्टतात थोड़ी ज्यादा रहेगी, आप फैमिली को समर्थक द दे पायेंगे। इस राशि के व्यक्ति गिनती रुचि कला और अभिनय के क्षेत्र में है तो आज आपको सुनहला अवसर मिलने वाला है।
तुला राशि : आज का दिन आपके लिए उज्ज्वल रहेगा। आज आपको मेहनत का उचित फल मिलेगा, आपको मन प्रसन्न होगा। आज आपके दायित्व जीवन में खुशियां आएंगी, साथ ही किसी मेहनतान के आने से ये खुशी डबल हो जाएगी। आज आप घर से जुड़ा कोई अशुभ काम पूरा कर सकते हैं।
वृश्चिक राशि : आज का दिन आपके लिए मिलाजुल रहने वाला है। आज आप जटिलताओं में कोई भी काम करने से बचें, तो आपके लिए अच्छा होगा। आज माता-पिता से आपको गिन्तनी की बड़ी सीख मिलेगी, जो आपकी तटवर्ती में सहायक सिद्ध होगी। आज आपका मन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी।
धनु राशि : आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं, गिनका लाभ लेकर आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। आज आपको लम्बे समय बाद घर जाने का मौका मिलेगा, सबसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। आज आपको किसी शारीरिक समस्या से मुक्ति मिलेगी आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे।
मकर राशि : आज का दिन आपके लिए पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। आज आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा, गिनके मार्गदर्शन से आपकी तटवर्ती होना तय है। आज आप इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति की उधेख न करें।
कुंभ राशि : आज का दिन आपके लिए सुहानुंगा रहने वाला है। आज आप समय से अपने अधिकतर काम पूरे कर लेंगे, जिससे आपके घर से काम का बोझ कम होगा। आज आप अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से न करें, खुद पर भरोसा रखें। आज आपको दोस्तों के साथ एजौय करने को मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न होगा।
मीन राशि : आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी सामाजिक समारोह में शामिल होंगे, आपके व्यवहार की सभी प्रशंसा करेंगे। इस राशि के इंजीनियर आज अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। आज आप खुद के अंदर बदलाव लेकर आयेंगे, जिसका आपको भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा।





भारत में कॉपीराइट कानून, नियम और नामांकन प्रक्रिया

इस दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर गाने, फिल्में, किताबें, ज्ञान और डिजाइन चोरी के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग बिना पूछे दस्तावेजों के दस्तावेज डाउनलोड कर लेते हैं और उसे अपने नाम से इंटरनेट पर दस्तावेज कमाते हैं। जिससे कलाकार, लेखक और उनके वास्तविक मतभेदों को बड़ा नुकसान होता है। और उन्हें उनकी मेहनत का सही फल नहीं मिलता। किसी और की बनी चीज को बिना पूछे इस्तेमाल करना कानून अपराध माना जाता है। इसलिए ऐसे मामलों की जांच के लिए ही कॉपीराइट कानून बनाया गया है ताकि कलाकारों का अधिकार सुरक्षित रहे और उनकी मेहनत का गलत फायदा न उठया जाए। आज के इस लेख में हमने आपको सभी उपयोगी वेबसाइटों से जोड़ा है, जैसे कि कॉपीराइट क्या है और यह क्यों जरूरी है? कॉपीराइट कानून के उल्लंघन की सजा, नियम और कॉपीराइट नामांकन कैसे करें – पूरी प्रक्रिया। अगर आपने अपनी मेहनत से कुछ बनाया है जैसे, किताब, गाना, वीडियो, सॉफ्टवेयर या कोई और चीज जिसमें आप चोरी होने से बचना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है।

कॉपीराइट क्या है और यह क्यों जरूरी है?

अगर आपने कोई किताब लिखी है, गाना बनाया है, फिल्म बनाई है, या कोई और नया काम किया है, तो जाहिर है, आपको लगता है कि आप अपनी किसी और मेहनत का इस्तेमाल बिना किए नहीं कर सकते। यही सुरक्षा कॉपीराइट देता है। सरल भाषा में कहा गया है कि कॉपीराइट सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है, जो आपकी बनाई गई वस्तु को अन्य लोगों द्वारा चुराया गया है या आपके सामान का उपयोग किए बिना बनाया गया है। आइए इसके बारे में आगे और भी विस्तार से जानें :-

कॉपीराइट क्यों जरूरी है?

आपकी मेहनत की सुरक्षा : अगर कॉपीराइट नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी कहानी, गाने या फिल्म को नकल लेकर अपना नाम दे सकता है। इससे आपको नुकसान होगा, कॉपीराइट आपकी मेहनत को हासिल है।

- कमाई का अधिकार : कॉपीराइट आपको यह अधिकार देता है कि आप अपनी बनाई हुई चीज से पैसे कमाएं। जैसे, अगर आपने एक किताब लिखी है, तो आपको केवल उसे छापने और बेचने (प्रिंट और बेचने) का हक मिलेगा। इसी तरह एक गायक अपने गाने से या एक फिल्म बनाने वाला व्यक्ति अपनी फिल्म से कमाई कर सकता है।

- चोरी और नकल पर कानूनी कार्रवाई : कॉपीराइट कानून यह तय करता है कि कोई भी व्यक्ति आपकी बनाई हुई चीज को बिना खोले इस्तेमाल या कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कदम उठा सकते हैं।
- काम-धंधे को स्थान : फिल्मों, संगीत, किताबें, सॉफ्टवेयर जैसी चीजें कॉपीराइट पर ही उपलब्ध हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो लाखों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी।

कॉपीराइट के प्रकार – यह किस पर लागू नहीं होता? भारत में कॉपीराइट अनपेक्षित रूप से लागू होता है :

- किताबें, लेख, कविता, निबंध, उपन्यास
- फिल्में, यूट्यूब वीडियो, वृत्तचित्र और सभी प्रकार के वीडियो संग्रह
- गाने, संगीत और रिकॉर्डिंग
- पेंटिंग, फोटोग्राफी और आर्ट वर्कशॉप
- सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम
- नाटक और नृत्य की प्रेमिका
- वेबसाइट का विवरण और डिजिटल डेटा आदि।

भारत में कॉपीराइट कानून और नियम

भारत में कॉपीराइट कानून यह तय करता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्मित सामग्री को कानूनी सुरक्षा मिले और उसके स्वामित्व के बिना कोई भी उसका उपयोग न कर सके। भारत में कॉपीराइट कानून कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत लागू होता है। समय-समय पर संशोधन



किए गए हैं ताकि यह नए समय की स्थिरता के खाते से बदला जा सके।

- कॉपीराइट अपने आप मिल जाता है : जब आपकी कोई नई चीज खराब हो, जैसे कोई कहानी, गाना, या पेंटिंग, तो उस पर आपका कॉपीराइट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप यूट्यूब पर कोई ऑरिजिनल वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर आपका कॉपीराइट लागू हो जाता है। यानी, वह वीडियो आपका है, और कोई भी उसे बिना आपके उपयोग के इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर देता है, तो यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी के तहत आप उस पर क्लेम कर सकते हैं या अपना वीडियो हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने वीडियो को कॉपीराइट कानून के तहत रजिस्टर करवाते हैं, तो आपके पास उसे अदालत में चुनौती देने का भी अधिकार होगा। इसलिए अधिक सुरक्षा के लिए कॉपीराइट रजिस्टर पर बहुत अधिक काम किया जा सकता है।
- कॉपीराइट कितना समय तक रहता है : अगर आपने कोई किताब या गाना बनाया है, तो आपके जन्म के बाद भी 60 साल तक उस पर आपका कॉपीराइट रहेगा। अगर आपने कोई फिल्म या डिजाइन बनाया है, तो उस पर भी 60 साल तक कॉपीराइट रहेगा।
- कॉपीराइट तोड़ना अपराध है : अगर कोई आपकी चीज को बिना पूछे इस्तेमाल करता है, या उसकी नकल (कॉपी) करके नकल करता है, तो यह कानूनी अपराध माना जाता है। ऐसा करने पर उस व्यक्ति के खिलाफ गैरकानूनी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- कॉपीराइट उल्लंघन पर सजा : अगर कोई आपकी बनाई हुई चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल (जेल) हो सकती है। उस पर 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना (जुर्माना) भी लगाया जा सकता है। अगर कोई बार-बार ऐसा करता है, तो साजा और

कीमती और भी बढ़ सकता है।

- फेयर यूज नियम : कुछ मामलों में आप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई चीज का बिना पूछे उपयोग कर सकते हैं, जैसे :
 - अध्ययन के लिए : यदि आप किसी पुस्तक के कुछ हिस्सों का अध्ययन (अध्ययन) के लिए उपयोग करते हैं, तो यह सही है।
 - खबरों के लिए : अगर आप किसी खबर (समाचार) में किसी की तस्वीर या वीडियो (फोटो या वीडियो) का इस्तेमाल करते हैं, तो यह सही है।
 - समीक्षा के लिए : यदि आप किसी फिल्म या गाने की समीक्षा (समीक्षा) करते हैं, तो आप उसके कुछ हिस्सों का उपयोग कर सकते हैं।
- ध्यान रखें, फेयर यूज का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी चीज को ही कॉपी कर लें। इसके अलावा जब भी आप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्मित वस्तु का उपयोग करते हैं तो उस व्यक्ति को क्रेडिट देना न भूलें। यदि आप किसी अन्य के गाने या वीडियो का छोटा भाग अपने वीडियो में उपयोग कर रहे हैं, तो नाम में उसका नाम और मूल लिंक जोड़ सकते हैं। इससे पता चलेगा कि उसका असली मालिक कौन है और आपका वीडियो कॉपीराइट उल्लंघन (कॉपी राइट उल्लंघन) से बच सकता है। इन सभी चीजों की जरूरतों के लिए कॉपीराइट नामांकन दस्तावेज, आय विवरण से जानें :-

- आपकी बनाई हुई चीज की कॉपी : इसका मतलब है आपके द्वारा बनाई गई चीज की प्रतिलिपि (कॉपी) जैसे कि किताब की पीडीएफ, गाने की एमपी3, वीडियो की एमपी4, पेंटिंग की जेपीईजी।
- अपनी पहचान का प्रमाण : जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
- अपने पासपोर्ट का प्रमाण (एड्रेस प्रूफ) : जैसे कि आधार कार्ड, बिजली का बिल।
- आवेदन फॉर्म XIV : यह एक नामांकन फॉर्म होता है जिसमें कॉपीराइट लेने के लिए भरना होता है।
- कॉपीराइट : कॉपीराइट के तहत अलग-अलग खाते

के लिए अलग-अलग फेसबुक अकाउंट होता है।

कॉपीराइट नामांकन कैसे होता है - पूरी प्रक्रिया

यदि आपने कोई किताब लिखी है, गाना बनाया है, वीडियो बनाया है, या कोई और अनोखा (मूल) काम किया है, तो आप कॉपीराइट लेकर उसे कानूनी रूप से सुरक्षित (सुरक्षित) कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कॉपीराइट कैसे लिया जाए? आइये इसे आसान भाषा में स्टेप-बाय-स्टेप समझें।

1. अपनी निर्मित वस्तु की श्रेणी (Category) चुनें :

सबसे पहले यह तय करें कि आपकी बनाई हुई चीज किस श्रेणी (कैटेगरी) में आती है। जैसे कि किताब, गाना, फिल्म, सॉफ्टवेयर, पेंटिंग आदि। हर चीज के लिए अलग-अलग कॉपीराइट श्रेणियां (कॉपीराइट श्रेणियां) मौजूद हैं, इसलिए सही श्रेणी को बहुत ही मान्यता प्राप्त है।

2.आवेदन प्रपत्र पढ़न :

- इसके बाद कॉपीराइट.जीओवी.इन की वेबसाइट और फॉर्म XIV को भरें।
 - इस फॉर्म में अपनी बनाई गई वस्तु का नाम, प्रकार, अपना नाम, पता और अन्य जानकारी भरें।
 - रचनाकार और स्वामी (निर्माता और स्वामी) की जानकारी, प्रकाशन (प्रकाशन की तिथि और स्थान (यदि लागू हो) जैसी जानकारी भी शिक्षण होगी।
 - कॉपीराइट शुल्क जमा करें : कॉपीराइट की फीस अलग-अलग होती है। आप इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं (डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से)। यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
 - किताब/लेख : लगभग 500/-
 - संगीत/गाना : लगभग 2000/-
 - फिल्म/वीडियो : लगभग 5000/-
 - उर्दू : लगभग 5000/-
 - आर्टवर्क/पेंटिंग : लगभग 2000/-
- इसकी फीस से जुड़ी अधिकाधिक व सटीक जानकारी के लिए आप कॉपीराइट की वेबसाइट पर जाकर अच्छे से

देख सकते हैं।

4. कलाकृतियाँ जमा करें :

- आपके द्वारा बनाई गई चीज की कॉपी (जैसे कि किताब की पीडीएफ, गाने की एमपी3, वीडियो की एमपी4, पेंटिंग की जेपीईजी)।
- अपनी पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)।
- अपने पासपोर्ट का प्रमाण (आधार कार्ड, बिजली का बिल)।
- यदि कोई वकील या एजेंट आपके लिए आवेदन कर रहा है, तो उसे पावर ऑफ अटॉर्नी वकील ही देगा।

5.आवेदन जमा करें और डायरी नंबर लें :

जब आप फॉर्म फॉर्म और कैटलॉग अपलोड करके आवेदन सबमिट कर देते हैं, तो आपको एक डायरी नंबर (डायरी नंबर) मिलता है। यह एक प्रकार का अपॉइंटमेंट नंबर 0 होता है, मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक (एप्लिकेशन स्टेटस ट्रैक) कर सकते हैं।

6. जांच और सलाह :

इसके बाद सरकार आपके आवेदन की जांच पड़ताल करेगी। इस प्रक्रिया में कई बार 2-6 महीने तक का समय लग सकता है।

7. कॉपीराइट धारक लें :

यदि सब सही रहता है और कोई आपत्ति (आपत्ति) नहीं आती है, तो सरकार आपका आवेदन मंजूर (अनुमोदन) कर सकती है। इसके बाद आपको कॉपीराइट प्रमाण पत्र (कॉपीराइट सर्टिफिकेट) मिल जाता है। यह प्रमाण पत्र यह सिद्ध करता है कि आप तैयार की गई चीज पूरी तरह से आपकी संपत्ति (संपत्ति) से ही है और अब कोई दूसरा इसे बिना आपकी इज्जत के इस्तेमाल नहीं कर सकता।

कॉपीराइट कितने समय तक वैध रहता है?

किताब, गाना, पेंटिंग, फिल्म, सॉफ्टवेयर आदि पर कॉपीराइट उसके मालिक के निधन के बाद 60 साल तक रहेगा। इसके बाद वह वस्तु सार्वजनिक (सार्वजनिक डोमेन) हो जाती है और कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। कॉपीराइट उल्लंघन की सजा और जुर्माना (कॉपीराइट उल्लंघन की सजा और जुर्माना) यदि कोई व्यक्ति किसी रचना को (जैसे - गाना, फिल्म, किताब, सॉफ्टवेयर, पेंटिंग आदि) को अपने स्वामित्व के बिना उपयोग करता है, कॉपी करता है, नकल करता है, या प्रकाशित करता है, तो यह कॉपीराइट उल्लंघन (कॉपीराइट उल्लंघन) कंपनी है। भारत में इसके लिए असोसिएट कानून बनाए गए हैं, जिसमें गहनों के तहत सजा और सजा की भरपाई हो सकती है।

1. कॉपीराइट उल्लंघन पर क्या सजा होती है?

अगर कोई व्यक्ति किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें दो तरह की सजा हो सकती है :

(ए) आपराधिक सजा (आपराधिक सजा)

अपराधी की सजा – कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले को 6 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है। हर्जाना-इस पर 50,000 से 2 लाख तक का हर्जाना लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बार-बार कॉपीराइट का उल्लंघन करता है, तो जेल की सजा 1 वर्ष से 3 वर्ष तक बढ़ सकती है और 1 लाख से 2 लाख तक की कटौती भी हो सकती है।

(बी) सिविल सजा (सिविल सजा)

कॉपीराइट मालिक अदालत में मामला अलग कर सकते हैं। जिसके लिए नुकसान की भरपाई (मुआवजा) करना होगा। इसके अलावा अदालत द्वारा बनाई गई अवैध कॉपीयां (पायरेटेड कॉपीयां) को जब्त करने का आदेश भी दिया जा सकता है।

2. कौन-कौन से काम कॉपीराइट उल्लंघन माने जाते हैं?

- बिना किसी की किताब, गाना, फिल्म, वीडियो, सॉफ्टवेयर आदि को कॉपी करना।
- किताब लाइसेंस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना (पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाना)।
- किसी की बनाई हुई असली चीज को अपने नाम से प्रकाशित करना या बेचना।
- फिल्में या फिल्में इंटरनेट पर बिना अपलोड या डाउनलोड करना।
- बिना उजाले के किसी की फोटो, आर्टवर्क या पेंटिंग को बाय द्वारा कॉपी करें।

कॉपीराइट उल्लंघन की याचिका कहां और कैसे करें?

यदि कोई आपकी बनाई हुई वस्तु का उपयोग आपके स्वामित्व के बिना कर रहा है, तो आप कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत दर्ज (शिकायत रजिस्टर) कर सकते हैं। नीचे आसान भाषा में बताया गया है कि आप कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं।

- ऑनलाइन शिकायत : आप भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.copyright.gov.in पर आवेदन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें : यदि कॉपीराइट चोरी ऑनलाइन (इंटरनेट) पर हुई है, जैसे कि किसी वेबसाइट, सोशल मीडिया या यूट्यूब पर, तो आप साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर शिकायत करें : यदि किसी ने यूट्यूब, फेसबुक, टेलीविज़न, ट्विटर या अन्य वेबसाइटों पर आपकी सामग्री चुराई है, तो आप सीधे उसी प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट कर सकते हैं।
- यूट्यूब पर कॉपीराइट शिकायत दर्ज करने के लिए : सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो में। इसके बाद कॉपीराइट अनुभाग में। यहां नई शिकायत दर्ज करें पर क्लिक करें, और प्रपत्र भेजें। यूट्यूब आमतौर पर 24-48 घंटे में कार्रवाई करता है और उस वस्तु को हटा देता है।
- निष्कर्ष :- कॉपीराइट उल्लंघन एक गंभीर अपराध है, जिससे हम सभी को बचना चाहिए। यह केवल कानूनी रूप से गलत नहीं है बल्कि यह किसी की मेहनत का भार उठाने के बराबर भी है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, तो हमेशा अपना लाइसेंस लें और कानूनी तरीके से काम करें। यदि आप कॉपीराइट से जुड़े किसी भी कानूनी मामले में संचर खते हैं या आपको कानूनी सलाह और सहायता की आवश्यकता है, तो हमारे अनुभवी वकीलों की टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। अभी हमसे संपर्क करें और अपनी समस्या का कानूनी समाधान प्राप्त करें!

शारदीय नवरात्रि 2026 का तीसरा दिन



शारदीय नवरात्रि 2026 का तीसरा दिन मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को है।

- इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की विधि-विधान से पूजा की जाती है।
- मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है।

- इनके दस हाथ हैं और इनका स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है।
- पूजा विधि और भोग
- रंग : इस दिन के लिए शुभ रंग का महत्व होता है, भक्त पारंपरिक रूप से विशिष्ट रंग के वस्त्र पहनते हैं।

- भोग : मां चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी चीजों (जैसे खीर, पेड़े या सफेद मिठाई) का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है।
- मंत्र : इस दिन के लिए शुभ रंग का महत्व होता है, भक्त पारंपरिक रूप से विशिष्ट रंग के वस्त्र पहनते हैं।

- महत्व : मान्यता है कि इनकी आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट, भय और बीमारियां दूर होती हैं तथा मन को शांति मिलती है। स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं दसों हाथों में खड्ग आदि शस्त्र धारण किए हुए मां हैं इनका पांचवा बाया हाथ वर मुद्रा में... शारदीय नवरात्रि 2026 के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त, मंत्र और आरती नीचे दी गई है :
- तिथि और शुभ मुहूर्त शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार को मनाई जा रही है।
- तृतीया तिथि प्रारंभ : 12 अक्टूबर 2026 को रात 10 :14 बजे से।
- तृतीया तिथि समाप्त : 13 अक्टूबर 2026 को रात 11 :29 बजे तक।
- पूजा का समय : सुबह के समय सूर्योदय के बाद ब्रह्म मुहूर्त या सुबह के सामान्य शुभ चौघड़िया मुहूर्त में मां चंद्रघंटा की पूजा करना उत्तम माना जाता है।
- मां चंद्रघंटा के सिद्ध मंत्र पूजा के दौरान आप इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जप कर सकते हैं :
- मूल मंत्र : देवी चन्द्रघण्टायै नमः॥
- प्रार्थना मंत्र : पिण्डजप्रवाराख्ढा चण्डकोपात्रकैर्युता। प्रसादं तनुते महां चंद्रघण्टेति विरुता॥
- स्तुति : या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
- 3. मां चंद्रघंटा की आरती पूजा संपन्न करने के बाद श्री का दीपक या कपूर जलाकर यह आरती गाएं : जय मां चंद्रघंटा सुख धाम। पूर्ण कीजो मेरे सखी काम॥ चंद्र समान तुम शीतल दाती। चंद्र तेज किरणों में समगती॥ श्रोत्र को शांत करने वाली। मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालिक मन भाती हो। चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली। हर संकट में बचाने वाली॥ हर बुधवार को तुझे ध्याए। श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए॥ मूर्ति चंद्र आकार बनाए। सन्मुख धी की ज्योति जलाए॥ शीघ्र शुक्रा कहे मन की बात। पूर्ण आस करो जगदाता॥ कांवीपूरस्थ स्थान तुम्हारा। कर्नाटक में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी। मत्त की रक्षा करो भवानी॥



यूएन को पूर्व पाक क्रिकेटर दानिश ने झाड़ा कहा- हिंदुओं के हालात पर कब बोलोगे

वाशिंगटन। राजधानी दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यूएनएचआरसी) द्वारा जताई गई चिंता पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कनेरिया ने यूएनएचआरसी से पूछा है कि वह बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और चीन में उइगर मुस्लिमों के दमन पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेगा। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली में हुए एक विशेष विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के लिए बयान जारी किया था। आयोग ने कहा था कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों से पहले और उनके दौरान प्रदर्शनकारियों, उनके नेताओं, सिविल सोसाइटी संगठनों के सदस्यों,



वकीलों और पत्रकारों को बड़ी संख्या में हिरासत में लिए जाने की खबरों से उन्हें चिंता है। आयोग ने भारतीय अधिकारियों से अपील की थी कि वे शांतिपूर्ण तरीके से

इकट्ठा होने के अधिकार का पूरा सम्मान करें और उसे सुनिश्चित करें। बयान में यह भी कहा गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर लगाई जाने वाली पाबंदियां जरूरत और

आनुपातिकता की कड़ी कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के इस बयान के सामने आने के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने हिंदुओं के हालात पर कब बोलोगे के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचारों और चीन के उइगर मुस्लिमों के दमन के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग कब अपनी चुप्पी तोड़ेगा? कब बोलोगे? बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर लंबे समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि वह पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों और चीन के उइगर मुस्लिमों के दमन को नजरअंजाम करता है। इस बीच, सोशल मीडिया पर कई

यूजर्स ने संयुक्त राष्ट्र के इस बयान पर सवाल उठाते हुए फांस में इस समय हो रहे हिंसक दंगों और प्रदर्शनों पर उसकी चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुल 7,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें देर रात तक धीरे-धीरे रिहा कर दिया गया। फिलहाल, प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठन के तीन प्रमुख चेहरे हिरासत में बने हुए हैं, जिन्हें कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी संगठन ने अगले दिन भी जंतर मंतर की ओर मार्च करने का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने भी आगामी 12 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

राष्ट्रपति ट्रंप के रूसी डीजल खरीदी के फैसले का अमेरिकी सांसद कर रहे विरोध

इस फैसले को रोकने के लिए एक द्विदलीय विधेयक पेश करने की घोषणा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूसी डीजल की खरीद पर लगी पाबंदियों को हटाने के फैसले का अब उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। रिपब्लिकन सांसद ब्रायन फिट्जजैट्रिक ने इस फैसले को रोकने के लिए एक द्विदलीय विधेयक पेश करने की घोषणा की है। उन्हें अपनी ही पार्टी के सांसद डॉन बेकन का भी समर्थन मिला है, जो इस विधेयक के सह-प्रस्तावक बनने के लिए तैयार हो गए हैं। यह मतभेद ऐसे समय में सामने आए हैं जब ट्रंप ने हाल ही में पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद रूसी डीजल की आपूर्ति का समझौता किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रायन फिट्जजैट्रिक, जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में कांग्रेसमल यूक्रेन काँकस के सह-अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बताया कि उनका नया विधेयक रूस से तेल की किसी भी प्रकार की खरीद को रोक लगाने के लिए लाया जाएगा और इसे रोनाल्ड रीगन पीस थ्रू स्ट्रेंथ

एक्ट नाम दिया जाएगा। फिट्जजैट्रिक ने यह भी संकेत दिया कि विधेयक को सदन में मतदान के लिए लाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उन्हें उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को सदन में भारी समर्थन मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन सांसद डॉन बेकन ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए एक्स पर लिखा- वह विधेयक के शुरुआती सह-प्रस्तावक बनने के लिए पहले ही सहमत दे चुके हैं। बेकन ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस को ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हालाँकि, इस विधेयक के पारित होने की राह आसान नहीं है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का मौजूदा कार्यकाल जनवरी में खत्म हो रहा है, जिससे सांसदों के पास विधेयक पर चर्चा करने और उसे पारित कराने के लिए बेहद सीमित समय बचा है। इस कारण यह पहल एक राजनीतिक संदेश देने तक सीमित रह सकती है, लेकिन यह दर्शाता है कि रूस नीति पर ट्रंप के दृष्टिकोण को उनके अपने ही दल में विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

पोलैंड के पीएम टस्क और रक्षामंत्री पर हमले की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

वार्सो। पोलैंड में पीएम डोनाल्ड टस्क और रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिश पर संभावित हमले की खबर ने देश भर में चिंता बढ़ा दी है। रिववार को पुलिस को इस खतरे से जुड़ा एक ईमेल मिला, जिसके बाद सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए और सुरक्षा एजेंसियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि ईमेल किसने भेजा है, हमले की कोई ठोस योजना थी या नहीं और खतरा कितना गंभीर है। हालाँकि, सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और कहा है कि धमकी को अंजाम दिए जाने की आशंका काफी ज्यादा थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड की खुफिया

सेवाओं की निगरानी करने वाले मंत्री के प्रवक्ता ने बताया कि अधिकारी इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। हमले से जुड़ी जानकारी सबसे पहले देश की सुरक्षा सेवा को मिली थी, जिसके बाद यह सूचना पुलिस को सौंप दी। उन्होंने संभावित साजिश से जुड़ी कोई अतिरिक्त जानकारी सार्वजनिक नहीं की। पोलिश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पीएम डोनाल्ड टस्क को रिववार सुबह सबसे पहले इस बेहद चिंताजनक खतरे के बारे में जानकारी दी गई। डोबर्ज़िंस्की ने यह भी उल्लेख किया कि पोलैंड की सुरक्षा एजेंसियों को हर महीने विभिन्न प्रकार की धमकियां मिल रही हैं, और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है।

नेपाल में बूढ़ी गंडकी नदी में भीषण बाढ़ की आशंका

काठमांडू। नेपाल में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक और भीषण बाढ़ आने की आशंका जलाई गई है, जिसके महेनजर राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने व्यापक चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने और तत्काल प्रभाव से ऊंचे तथा सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी चेतावनी में बताया है कि बूढ़ी गंडकी नदी में बड़ा बाढ़ का पानी आने वाला है। यह संभावित बाढ़ गोरखा जिले की चुमानुब्री ग्रामीण नगरपालिका-6 क्षेत्र से उत्पन्न हो सकती है। लोगों को त्रिशूली दोभान तक नदी के आसपास न जाने की सख्त हिदायत दी गई है, क्योंकि बाढ़ का पानी इन क्षेत्रों से होकर गुजर सकता है। विशेष रूप से स्थानीय निवासियों और नदी के किनारे मौजूद लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्रशासन की ओर से लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, भूस्खलन या नदी के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट के कारण अचानक बाढ़ आना आम बात है। ऐसी स्थिति में नदी का जलस्तर बहुत कम समय में तेजी से बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है।

सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया

रियाद। सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष के बीच सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने एक ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गठबंधन के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि यमन के हूती समूह की ओर से दागे गए एक ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन को सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में इंटरसेप्ट किया गया, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल को हुतियों ने दक्षिण-पश्चिमी सऊदी अरब के खमोस मुशैत शहर की ओर दागा था। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी विमान अधिकारियों ने बताया कि रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए एक हमले में पाकिस्तान के एक नागरिक की मौत हो गई और 11 घायल हुए।

पाकिस्तान के जिवानी तट पर बीएलए कोस्ट गार्ड्स ने नाव पर बरसाई गोलियां

करांची। पाकिस्तान के ग्वादर जिले के जिवानी तट के पास अरब सागर में गश्त कर रही कोस्ट गार्ड्स की एक नाव पर गोलीबारी हुई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स के चार जवानों को मार गिराया। हालाँकि पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों ने इस दावे को खारिज कर दिया, उनका कहना है कि गोलीबारी में कुछ जवान घायल हुए हैं, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक यह घटना तब हुई जब पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की टीम तस्करी के संदेह में कुछ नावों को रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान नाव पर मौजूद जवानों पर अचानक गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के बाद हमलावर तट की ओर भाग गए। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में कुछ

हमलावर भी हताहत हुए हैं, हालाँकि उनकी संख्या की पुष्टि नहीं की गई है। इस तरह, घटना में जानमाल के नुकसान को लेकर दोनों पक्षों के दावों में स्पष्ट विरोधाभास है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा अधिकारी अब इस बात की भी गहन जांच कर रहे हैं कि क्या इस हमले का संबंध समुद्री इलाके में सक्रिय तस्करी नेटवर्क से है। जांच से जुड़े सूत्रों को शक है कि अवैध तस्करी के रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस हमले की योजना बनाई गई हो सकती है। घटना के बाद जिवानी के तटीय इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। अधिकारियों ने हमलावरों की तलाश और पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह हमला पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर बलूचिस्तान प्रांत में, जहां अलगाववादी संगठन लंबे समय से सक्रिय हैं।

भारतीय पायलट कैप्टन स्मित को इजरायल का सर्वोच्च सम्मान

तेलअवीव। भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों बेकसूर यात्रियों की जान बचाने के लिए इजरायल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान, 'इजरायली प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर सिविलियन हीरोइज्म' से नवाजा जाएगा। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने कैप्टन स्मित को पत्र लिखकर उन्हें 'भारत, इजरायल और पूरी मानवता का हीरो' बताया है।यह असाधारण घटना 30 सितंबर को हुई, जब फ्लाईइंबुई की एक उड़ान के दौरान ओमानी को-पायलट हमाम अल-हम्मामी ने कैप्टन स्मित मच्छर पर हमला कर दिया। को-पायलट का इरादा विमान को 174 इजरायली नागरिक सहित सैकड़ों लोग सवाा थे। उसने कैप्टन स्मित के सिर पर कई बार किए और कुल्हाड़ी से उनका हाथ खून-खूनकर कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, कैप्टन स्मित ने अद्भुत साहस दिखाते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिससे यात्रियों और कुछ अन्य पायलटों ने मिलकर हमलावर को काबू कर लिया।

सक्षिप्त समाचार

समंदर में भी सुरक्षित नहीं रहा पाकिस्तान,

बीएलए ने कोस्ट गार्ड्स की टीम पर किया हमला

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अरब सागर तट पर सुरक्षा बलों को नई चुनौती का सामना करना पड़ा है, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने कोस्ट गार्ड्स की एक टीम पर समुद्री हमले को अंजाम दिया है। यह घटना दिखाती है कि अलगाववादी संगठन अब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी चुनौती दे रहे हैं। यह हमला पाकिस्तान के ग्वादर जिले के जिवानी तट के पास समुद्री इलाके में हुआ, जब पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की नाव नियमित गश्त पर थी। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, टीम तस्करी के शक में कुछ नावों को रोकने पहुंची थी, तभी उन पर भारी गोलीबारी शुरू हुई। जवानों ने भी तुरंत जवाबी फायरिंग की और दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के बाद हमलावर तट की ओर भाग गए। सुरक्षा सूत्रों का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में कुछ हमलावर भी हताहत हुए, हालाँकि उनकी संख्या स्पष्ट नहीं की गई है। हमले की जिम्मेदारी लेकर अलगाववादी संगठन बीएलए ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के चार कर्मियों को मार गिराया है। दूसरी ओर, पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों ने दावे को खारिज कर कहा कि मुठभेड़ में कुछ जवान घायल हुए हैं, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है। इस तरह, घटना में जानमाल के नुकसान को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं और विरोधाभासी बने हुए हैं। सुरक्षा अधिकारी अब इस बात की भी गहनता से जांच कर रहे हैं कि इस समुद्री हमले का क्षेत्र में सक्रिय तस्करी नेटवर्क से कोई संबंध तो नहीं है। जांच से जुड़े सूत्रों को शक है कि अवैध तस्करी के रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए इस हमले की योजना बनाई गई होगी। घटना के बाद जिवानी के तटीय इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अधिकारियों ने सर्वेक्षणों की तलाश में जांच एवं तलाशी अभियान तेज कर दिया है। यह घटना पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा पर बढ़ते खतरों को उजागर करती है।

ब्रिटिश पीएम का बड़ा दावा : 2016 के बैकजट

जनमत संग्रह में रूस का सीधा दखल

लंदन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंजी बर्नहेम ने महत्वपूर्ण बयान में दावा किया है कि 2016 के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए हुए जनमत संग्रह में रूस ने स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप किया था। पीएम बर्नहेम ने बताया कि जुलाई में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद, उन्होंने अपने सलाहकारों से इस बारे में पूछा था, और उन्हें हाँ, ऐसा हुआ था का स्पष्ट जवाब मिला। यह पहली बार माना जा रहा है जब ब्रिटेन के किसी प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से ब्रेकिंगट जनमत संग्रह में रूसी दखलंदाजी को स्वीकार किया है। बर्नहेम ने जानकारी को आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड में दर्ज करने के महत्व पर जोर दिया। उनका तर्क है कि इससे जर्मनी और फ्रांस जैसे पूरे यूरोप के देशों के मतदाताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि कुछ राजनीतिक गतिविधियां रूस जैसे दुश्मनों द्वारा उकसावे में शुरू की जाती हैं। यह टिप्पणी उस समय में आई है जब ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में रूस के बढ़ते हस्तक्षेप के खतरे को लेकर लगातार चेतावनी दे रही हैं। हालाँकि, रूस लंबे समय से इन आरोपों का खंडन करता रहा है और अन्य देशों के चुनावों या जनमत संग्रहों में हस्तक्षेप से इंकार करता है। प्रधानमंत्री बर्नहेम ने बीते सप्ताह जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मर्ज ने उनसे कहा कि जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) के रूस से स्पष्ट संबंध हैं और वित्तपोषण भी मिलता है। बर्नहेम ने कहा कि जर्मनी की राजनीति में गलत और भ्रामक सूचनाएं निश्चित रूप से रूस से आ रही हैं। यह मुद्दा 2020 में भी सामने आया था, जब संसद की खुफिया एवं सुरक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार की इस विफलता पर सवाल उठाया था कि वह जनमत संग्रह पर रूसी राज्य मीडिया और ट्रोल् खातों के संभावित प्रभाव का पूरी तरह आकलन क्यों नहीं कर पाई थी।

रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल प्रभाव से ऊर्जा युद्धविराम, इसे तोड़ना मत!

कीव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल प्रभाव से ऊर्जा युद्धविराम लागू होने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गए हैं और उन्हें इस समझौते को तोड़ना नहीं चाहिए। इस ऊर्जा युद्धविराम का मतलब है कि अब रूस और यूक्रेन एक-दूसरे के ऊर्जा ठिकानों, जैसे पेट्रोल डीजल या तेल से जुड़ी रिफाइनरियों और ढांचों पर हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा इसे मत तोड़ना। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घोषणा के तहत युद्धविराम की अवधि और उसकी विस्तृत शर्तों के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा पर हैरानी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि युद्धविराम की घोषणा उनके लिए भी नई खबर थी, यानी उन्हें इसकी पूर्व जानकारी नहीं थी। जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के लिए सहमत होता है, तो यूक्रेन को इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ट्रंप से इस युद्धविराम के शुरू होने की तारीख बताने का आग्रह भी किया। बता दें यह घटनाक्रम जेलेंस्की के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर रूस यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले रोक देता है, तो यूक्रेन भी रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमले बंद कर देगा। जेलेंस्की ने युद्ध में तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने और इसके लिए ठोस गारंटी की आवश्यकता पर जोर दिया था। ट्रंप की यह पहल उनके उस हालिया बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने अमेरिका में डीजल की ऊंची कीमतों के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया था और यूक्रेन में राष्ट्रपति बदले जाने की जरूरत बताई थी। ऊर्जा युद्धविराम की घोषणा से पहले, यूक्रेन रूस के अंदर बुनियादी ढांचे की निशाना बनाने का अभियान तेज कर रहा था, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण रूस की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी यैंटेक्स का एक डेटा केंद्र बंद हो गया था।

कनाडा पीएम ने रूस से की ऊर्जा संघर्ष

विराम समझौते का पालन करने की अपील

ओटावा। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने बताया कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत हुई है। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र के हालात और यूक्रेन युद्ध की तेजी से बदलती स्थिति पर चर्चा हुई। कार्नी ने रूस से अमेरिका के मददगारों के साथ संघर्ष विराम समझौते का पालन करने की अपील की। मार्क कार्नी ने एक्स पोस्ट पर लिखा- सुबह मेरी बातचीत राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई। दोनों नेताओं के साथ हुई बातचीत में हमने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हालात और यूक्रेन में चल रहे युद्ध की तेजी से बदलती स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच जिस नए ऊर्जा संघर्षविराम की कोशिश की जा रही है, उससे युद्ध का तनाव काफी हद तक कम हो सकता है और हजारों नागरिकों को नुकसान से बचाया जा सकता है। उन्होंने ओर लिखा- , कनाडा रूस से इस समझौते का पालन करने की अपील करता है, साथ ही मम अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर यूक्रेन और यूरोप के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते रहेंगे। ट्रंप ने रविवार को रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष को लेकर एनर्जी सीधफायर दावा किया है। ट्रंप ने दृढ़ता से सोशल पर इसकी जानकारी दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पोस्ट में लिखा- , अभी से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में एनर्जी सीधफायर लागू हो गया है। दोनों पक्ष इस पर सहमत हैं। इसे न तोड़ें। वही, क्लाइट हाउस ने राष्ट्रपति ट्रंप की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि तत्काल प्रभाव से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में ऊर्जा संबंधी युद्धविराम। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर रोक लगाता है तो यूक्रेन रूसी तेल रिफाइनरियों पर अटैक रोकने को तैयार है।

बल्लेबाज सुदर्शन रणजी ट्रॉफी मैच में चोटिल हुए

न्यूजीलैंड दौरे से पहले टीम प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ीं



नई दिल्ली। तमिलनाडु की ओर से रणजी ट्रॉफी में उतरे बल्लेबाज साई सुदर्शन राजस्थान के खिलाफ मुकाबले के दौरान चोटिल हो गये हैं। इससे भारतीय टीम की भी मुश्किले बढ़ गयी है क्योंकि सुदर्शन न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम में शामिल हैं। राजस्थान के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलते हुए सुदर्शन ने जब वह कवर क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे तभी उन्हें गेंद को रोकने के प्रयास में ये चोट लगी। एक रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के बल्लेबाज करण लांबा के शाट को रोकने के प्रयास में वह मैदान पर गिर गये थे। तमिलनाडु

टीम के फिजियो और एक सहयोगी स्टाफ के एक सदस्य ने उन्हें मैदान से बाहर जाने में सहायता की। हालांकि राहत की बात ये है कि सुदर्शन की चोट गंभीर नहीं है। बताया गया कि गेंद उनके घुटने पर लगी थी। मैदान से बाहर आने के बाद उन्हें डगआउट में बर्फ से सिकाई करते हुए देखा गया। हालांकि, उनकी फिटनेस को लेकर अंतिम स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि दर्द कितनी जल्दी कम होता है। राजस्थान की पहली पारी समाप्त होने के बाद तमिलनाडु की बल्लेबाजी के दौरान सुदर्शन के बल्लेबाजी करने की संभावना इस पर निर्भर

हमारे गेंदबाजों ने योजना के अनुसार काम किया : नीतीश रेड्डी

इंदौर। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय टीम की 14 रनों की रोमांचक जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि हमारे गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने 224 रनों के विशाल लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया, जिससे यह इस वेस्टइंडीज दौरे पर पहला मौका रहा जब रनों का पीछा करने वाली टीम को हार का सामना करना पड़ा। नीतीश ने इस मैच में 21 रन भी बनाये। अपनी गेंदबाजी से 19 रन देकर एक अहम विकेट भी लिया। मैच के बाद कहा, नीतीश ने टीम के मनोबल और रणनीति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, जीत तो जीत होती है। हम सभी को अपनी कोशिशों पर गर्व है। हम जानते हैं कि यह आसान नहीं था पर हमारे गेंदबाजों ने योजना को बहुत अच्छे से लागू किया। रेड्डी ने बताया कि अंतिम ओवरों में वेस्टइंडीज को प्रत्येक ओवर में 14 रनों की दर से

रन बनाने थे। उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में, भारतीय गेंदबाजों की योजना साफ थी। हमने सोचा कि अगर हम हर गेंद पर सिर्फ एक रन ही दें, तो यह हमारे लिए काम करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमेशा विकेट लेने की कोशिश करना ही एकमात्र रणनीति नहीं होती। हम विकेट लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे। कभी-कभी डिफेंसिव योजना भी काम करती है। उन्होंने कसान के स्पष्ट निर्देशों का भी जिक्र किया, जिसके तहत टीम को अपनी योजना पर टिके रहना था और अपनी फील्डिंग के हिसाब से गेंदबाजी करनी थी। उन्होंने कहा, अगर हमें छक्का भी लग जाए, तो भी हमें अपनी योजना पर ही टिके रहना होगा।, यह दिखाता है कि टीम ने किस तरह दबाव में भी अनुशासन बनाए रखा। भारतीय गेंदबाजों ने रनों की गति को नियंत्रण में रखा और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर फेंकी, जिससे वेस्टइंडीज लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही।

राष्ट्रीय गारिमा



राष्ट्रीय गारिमा

करेगी कि वह कितने ठीक हुए है। सुदर्शन के चोटिल होने की खबर ऐसे समय आई है, जब भारतीय टीम लाल गेंद मुकाबलों की तैयारियां चल रही हैं। सुदर्शन हाल ही में पैर के अंगुठे की चोट से उबरकर इंडिया ए की टीम में लौटे थे। वह शुरुआत में तमिलनाडु की रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पुडुचेरी में खेलने के बाद शनिवार रात जयपुर पहुंचे। इसके बाद उन्हें तमिलनाडु की अंतिम ग्यारह में शामिल किया गया और उन्होंने पहले दिन मैदान पर भी हिस्सा लिया।

24 वर्षीय सुदर्शन की फिटनेस आगामी मुकाबलों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले इंडिया ए के रेड-बॉल मुकाबलों की योजनाओं में शामिल किया गया है। ये मैच 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में उनकी चोट की स्थिति यह तय करने में अहम होगी कि वह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मैदान पर उतर पाएंगे या नहीं। सुदर्शन इससे पहले पैर के अंगुठे की चोट के कारण भारत के श्रीलंका दौरे से बाहर रहे थे। उनकी फिटनेस को लेकर चिंताओं के बावजूद उन्हें टीम में शामिल किया गया था।

केरला ब्लास्टर्स ने आईएसएल में जीत से शुरुआत की

पहले ही मुकाबले में इंटर काशी को 2-0 से हराया

पुणे। केरला ब्लास्टर्स एफसी ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2026-27 फुटबॉल में जीत से सत्र की शुरुआत की है। पहले अपने पहले ही मैच में इंटर काशी को 2-0 से हराया। इस जीत के साथ ही केरला ब्लास्टर्स को में तीन अंक मिले हैं। केरला ब्लास्टर्स ने इंटर काशी के खिलाफ मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। विविन मोहनन ने केरला की ओर से मैच का पहला गोल 18वें मिनट में किया। इससे , केरला ब्लास्टर्स को मुकाबले में 1-0 की बढ़त मिल गयी। पहला गोल होने के बाद इंटर काशी ने बराकरी का प्रयास शुरु कर दिया पर उसे सफलता नहीं मिली। इंटर के मनवीर सिंह ने कई अवसरों पर केरला ब्लास्टर्स की रक्षापंक्ति को तोड़ने का प्रयास किया। 35वें मिनट में मनवीर ने गोल दागने के करीब पहुंच गये लेकिन केरला के गोलकीपर अशं शेख ने इस प्रयास को विफल कर दिया। इस प्रकार पहले हाफ



में इंटर काशी गोल करने में असफल रही। वहीं दूसरे हाफ की शुरुआत के बाद केरला ब्लास्टर्स ने अपनी बढ़त को बेहतर करने का प्रयास किया। स्थानापन खिलाड़ी मोमो यानसाने और आंद्रे ग्रीन ने गोल करने के प्रयास किये पर विफल रहे। इंटर काशी ने दूसरे हाफ में मुकाबले को बराबर करने के लिए लगातार प्रयास किए। 61वें मिनट में मनवीर ने हेडर के जरिए गोल दागने का प्रयास किया पर केरला के गोलकीपर ने उसे विफल कर दिया। वहीं मुकाबले के अंतिम क्षणों में केरला ब्लास्टर्स की ओर से ग्रीन ने गोल दागकर अपनी टीम की बढ़त 2-0 हो गई जो अंत तक बनी रही।



व्यापार समाचार

संक्षिति समाचार

रुपया 91 पैसे उछलकर 95.80 प्रति

डॉलर पर खुला

मुंबई। 12 अक्टूबर (भाषा) रुपया सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शुरुआती कारोबार में 91 पैसे मजबूत होकर 95.80 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुद्रा विनिमय बाजार में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाने के बाद घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला है। केंद्रीय बैंक ने शनिवार को कई उपायों की घोषणा की थी। इनमें नामित बैंकों के जरिये तेल विपणन कंपनियों के लिए डॉलर की अलग व्यवस्था और विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव वाले कुछ सौदों की लागत बढ़ाना शामिल है। इन कदमों का उद्देश्य हाजिर बाजार में डॉलर की मांग घटाना और सट्टेबाजी वाली कारोबारी स्थितियों पर अंकुश लगाना है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि इन उपायों से कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मजबूत डॉलर के दबाव के बावजूद भारतीय मुद्रा को संभलने में मदद मिलने की उम्मीद है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया मजबूत होकर 95.61 प्रति डॉलर पर खुला। शुरुआती कारोबार में इसकी बढ़त कुछ कम हुई और यह 95.80 प्रति डॉलर पर कारोबार करने लगा जो पिछले बंद भाव के मुकाबले इसमें 91 पैसे की तेजी है। रुपया शुक्रवार को 17 पैसे की बढ़त के साथ 96.71 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इससे एक दिन पहले यह 13 पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले 96.88 के रिकॉर्ड निचले बंद स्तर पर पहुंच गया था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 101.94 पर रहा।

भारतीय शेयर बाजार की

मजबूत शुरुआत

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को मजबूत शुरुआत की है। वैश्विक स्तर पर मिले-जुले संकेतों के बावजूद, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों ने शुरुआती कारोबार में महत्वपूर्ण बढ़त दर्ज की। निवेशकों की नजर कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर बनी हुई है, जबकि अमेरिका और रूस के बीच हुई एक अहम तेल आपूर्ति डील ने बाजार को सकारात्मक दिशा दी है। सुबह के कारोबार में निफ्टी निफ्टी 22,628 के स्तर पर कारोबार करते हुए नजर आया, जो भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक संकेत था। हालांकि, दक्षिण कोरिया और ताइवान के बाजारों में गिरावट देखी गई, वहीं जापान का निक्केई बंद रहा। दूसरी ओर, अमेरिकी बाजार पिछले सत्र में हरे निशान में बंद हुए थे, जिससे थोड़ी राहत मिली। ब्रेंट क्रूड का भाव 103 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है, जबकि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 102 के स्तर पर है। निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर अमेरिका और रूस के बीच तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं कुछ हद तक कम हुई हैं। घरेलू मोर्चे पर भारतीय शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 361.65 अंक बढ़कर 72,833.98 पर और निफ्टी 122.05 अंक की तेजी के साथ 22,642.50 पर कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार में 1,921 शेयरों में तेजी दर्ज की गई, जबकि 733 शेयरों में गिरावट रही। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में करीब 1 फीसदी का उछाल आया, जिसमें ट्युब इन्वेस्टमेंट, बजाज ऑटो और अशोक लेलैंड जैसे शेयरों ने बढ़त बनाई। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, जियो फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और इंडिगो निफ्टी के प्रमुख गेनर रहे, वहीं टेक महिंद्रा, एस्बीआई, एंक्सिस बैंक जैसे शेयरों में कुछ गिरावट देखी।

अक्टूबर में प्रतिदिन औसत कमी 2.4 लाख टन से घटकर 60,000 टन हुई

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश के ताप बिजलीघरों में कोयले के भंडार घटने की रफ्तार में अक्टूबर महीने के पहले दस दिनों में भारी कमी आई है, जिससे ऊर्जा संकट की आशंकाएं कम हुई हैं। सरकार ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि कोयले की आपूर्ति बेहतर होने के कारण अब दैनिक खपत के अनुरूप उपलब्धता बनी हुई है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 29 सितंबर से कोयले का भंडार लगातार 1.8 करोड़ टन से ऊपर बना हुआ है, जो स्थिति में स्थिरता का संकेत है। कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 29 सितंबर को बिजलीघरों में कोयले का भंडार 1.8932 करोड़ टन था, जो



10 अक्टूबर को घटकर 1.8205 करोड़ टन रहा गया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सितंबर में बिजलीघरों में कोयले का भंडार निचले स्तर पर आ गया था। सितंबर में पूरे महीने कोयले

का भंडार करीब 72.8 लाख टन घटा था, इस दौरान औसतन प्रतिदिन करीब 2.4 लाख टन की कमी आई थी। वहीं, अक्टूबर के पहले 10 दिन में कुल मिलाकर केवल 5.6 लाख

टन कोयला घटा, जिससे प्रतिदिन औसतन लगभग 60,000 टन की कमी दर्ज की गई। यह सितंबर की तुलना में चार गुना से अधिक धीमी रफ्तार है, जो आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है। कोयला मंत्रालय ने इस सकारात्मक बदलाव का श्रेय मालगाइडियों में कोयला लादने की संख्या बढ़ने को दिया है। इस वर्ष एक से 10 अक्टूबर के दौरान बिजली क्षेत्र के लिए प्रतिदिन औसतन 469 रैंक कोयला लादा गया, जबकि सितंबर में यह औसत 426 रैंक था, इसमें करीब 10 प्रतिशत का वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, अक्टूबर में बिजली क्षेत्र को प्रतिदिन औसतन 24.9 लाख टन कोयले की वास्तविक आपूर्ति हुई, जबकि सितंबर में यह 22.1 लाख टन प्रतिदिन थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि चालू महीने में 10 अक्टूबर तक कोयले की वास्तविक

आपूर्ति निर्धारित योजना (23.7 लाख टन प्रतिदिन) से अधिक रही, जिसमें 10 में से नौ दिन लक्ष्य से ऊपर आपूर्ति हुई। मंत्रालय ने कहा कि वह पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), रेल मंत्रालय और बिजली कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कम भंडार वाला बिजलीघरों में आपूर्ति पर करीबी नजर रखी जा रही है और जरूरत के आधार पर कोयले का पुनर्वितरण भी किया जा रहा है, ताकि पर्याप्त आपूर्ति तथा निर्बाध बिजली उत्पादन सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय ने कोयले की उचित आवाजगही सुनिश्चित करने में भारतीय रेलवे के लगातार सहयोग और पेशेवर प्रतिबद्धता की विशेष रूप से सराहना की है।

सीमेंट की कीमतों में भारी उछाल संभव, घर बनाना होगा महंगा

नई दिल्ली। देश में घर बनाने वालों और निर्माण उद्योग को जल्द ही महंगाई का एक और झटका लग सकता है। एमके रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगातार बढ़ती इनपुट लागत और मजबूत मांग के दबाव में सीमेंट कंपनियां अक्टूबर के मध्य से प्रति बैग 10 से 15 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 अक्टूबर से यह बढ़ोतरी पश्चात् होने की प्रबल संभावना है। कंपनियों के लिए ईंधन (पेटकोक, आयातित कोयला) और पैकेजिंग सामग्री (पॉलीप्रोपाइलीन ग्रेन्यूल) की लागत पिछले 6-7 महीनों से लगातार बढ़ रही है। पेटकोक और आयातित

कोयले के स्पॉट भाव पिछली तिमाही की तुलना में क्रमशः लगभग 20 फीसदी और 16 फीसदी अधिक हैं। पहली तिमाही में की गई मामूली मूल्य वृद्धि इन खर्चों की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिसे जुलाई-अगस्त में मॉनसून के कारण आई कीमतों में गिरावट ने और बढ़ा दिया। हालांकि, मजबूत बिक्री (बॉल्युम ऑफ़सेट) इस सेक्टर को संभारा दे रही है। गैर-व्यापारिक मांग, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आगामी चुनाव से पहले की गतिविधियों के कारण खपत अच्छी बनी हुई है, और आगले डेढ़ साल तक इसमें तेजी बनी रहने की उम्मीद है।

यूपीआई शुल्क वृद्धि से ग्राहकों पर अप्रत्यक्ष बोझ : आईआईटी रिपोर्ट

नई दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे की एक रिपोर्ट ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के लिए प्रस्तावित संशोधित शुल्क ढांचे पर गंभीर चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, इस नए ढांचे से ग्राहकों पर अप्रत्यक्ष रूप से खुदरा कीमतों में वृद्धि का बोझ पड़ सकता है, भले ही व्यापारियों को सीधे शुल्क लगाने से रोका गया हो। रिपोर्ट का अनुमान है कि मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) स्ट्रक्चर से पैमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को सालाना करीब 18,000 करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है। हालांकि, रिपोर्ट चेतावनी देती है कि व्यापारी इस अतिरिक्त खर्च को अपनी कीमतों में शामिल कर सकते हैं, जिससे 2,000 रुपये से कम के ट्रांजेक्शन करने वाले ग्राहकों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लागत उठानी पड़ेगी। आईआईटी रिपोर्ट ने मौजूदा ढांचे में बदलाव की मांग करते हुए कहा है कि अन्यथा यूपीआई लोगों का

भरोसा खो सकता है। संशोधित ढांचे के तहत, 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेन्ट पेमेंट पर 0.40 फीसदी तक एमडीआर लागेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी, जबकि 2,000 रुपये तक के भुगतान और पी2पी ट्रांसफर मुक्त रहेंगे। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि बैंकों को अपने बड़े नेट इंटरस्ट मार्जिन (7वित्त वर्ष 26 में 4.84 लाख करोड़ रुपये) से सालाना लगभग 15,000 करोड़ रुपये यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योगदान देना चाहिए। यह भी मांग की गई है कि ब्रह्म संग्रह जैसे लेनदेन को एमडीआर से छूट दी जाए। रिपोर्ट ने 50 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले ऑनलाइन व्यापारियों पर ही शुल्क लगाने, एमडीआर को 40 रुपये तक सीमित करने और राजस्व को यूपीआई के विस्तार व सुरक्षा में लगाने का प्रस्ताव दिया है, ताकि डिजिटल भुगतान में ग्राहकों का हित सुरक्षित रहे।

राजधानी

व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

अरेरा कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई नहीं होने से रहवासी नाराज

भोपाल। राजधानी भोपाल के अररा कॉलोनी सहित अनार आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को लेकर विवाद फिर सामने आया है। रहवासियों का आरोप है कि आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित भूखंडों पर व्यवसायिक गतिविधियाँ जारी हैं, लेकिन सर्वोच्च मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। सोमवार को संसद रहवासी संघर्ष समिति ने नगर निगम हकिश्टर संस्कृति जैति को पत्र सौंपकर कहकर को आदेश का पालन करने और नियमों का उल्लंघन करने वाली संघितियों पर कार्रवाई को मांग की। समिति ने पत्र के साथ हाईकोर्ट के 8 सिविल कोर्ट को पारित आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की



प्रतियां भी प्रस्तुत कीं। समिति के अनुसार, हाईकोर्ट ने संबंधित मामले में पक्षकारों का सुनवाई का अवसर देने, भू-उपयोग और अनुमतियों की जांच करने तथा निर्धारित चार सप्ताह की समय-सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। रहवासियों का

कहना है कि इसके बावजूद अरेरा कॉलोनी में कथित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई नहीं होने से उनकी नाराजगी बढ़ रही है। संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति का कहना है कि संबंधित संपत्तियों के स्वीकृत नक्शों,

आवश्यक विलेख और अन्य दस्तावेजों में आवेष्टी उपयोग दर्ज होने के बावजूब व्यावसायिक गतिविधियों को जाा रही हैं। समिति ने स्पष्ट किया कि किसी संघर्ष को फ्रीहोल्ड करने माा संघ व्यावसायिक गतिविधियों संघर्षात करने को अनुमति नहीं मिल जाती। इसके लिए संबंधित नियमों के तहत जरूरी अनुमतिां होना भी आवश्यक है। समिति ने यह भी कहा कि प्रस्तावित मास्टर प्लान-2047 का हवाला देकर मौजूदा व्यावसायिक गतिविधियों को स्वतः वैध नहीं माना जाा चाहिए। समिति के दावे के अनुसार, संबंधित क्षेत्र को प्रस्तावित योजना में आरजी-3 श्रेणी के तहत आवेष्टी रखा गया है। ऐसे में प्रत्येक संघ के वास्तविक भू-उपयोग, भवन अनुमति और अन्य वैधानिक

दस्तावेजों को जांच की जानी चाहिए। सुभिखित ने अरेरा कॉलोनी में आवासीय भूमिदों पर व्यावसायिक गतिविधियों के मामलों में वृद्धि का दावा किया है। उसके मुताबिक, वर्ष 2022 में ऐसे करीब 20 मामलों सामने आए थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 80 से अधिक हो गई है। सुभिखित ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में सील की गई कुछ संघर्षों को दोबारा व्यावसायिक गतिविधियों संचालित होने को शिकायतें मिल रही हैं। रहवासीयों ने आशंका जताई कि मास्टर प्लान-2047 लागू होने से पहले कुछ लोगों कथित अवैध व्यावसायिक निर्माणों को नियमित कराने का प्रयास कर सकते हैं। सुभिखित ने मांग की कि ऐसे मामलों में नियमों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही निर्णय लिया जाए।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 55 लाख रुपये की साइबर ठगी का खुलासा



**पुलिस ने तीन आरोपियों को किया
गिरफ्तार, 20 लाख रुपये की राशि होल्ड**

भोपाल। मध्यप्रदेश में साइबर अपराधों के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई को जारी रखा है। इसी क्रम में रतलाम पुलिस ने एक डिजिटल अपराध के नाम पर 55 लाख रुपये की साइबर ठगी के प्रकरण का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिसस्थान की त्वरित कार्रवाई से ठगी की राशि में से लगभग 20 लाख रुपये होल्ड कराने में सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपियों में से दो आरोपियों को हैदराबाद तथा एक आरोपी को धारवाड़, कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। प्रकरण में दो फरियादी, जो कुवैत में मोटर पार्ट्स का

व्यवसाय करते हैं और वर्तमान में तलामा में रहे रहे थे, को 15 सितंबर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर स्वयं को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया गया। कॉल करने वाले ने मोबाइल नंबर के कविवर्य अपाराधिक उपयोग तथा पॉक्सिजन का आईएसएसएस से जुड़े व्यक्ति से वातचीत जैसे गंभीर आरोप लगाकर फरियादी को भयभीत किया। इसके बाद अलग-अलग मोबाइल नंबरो से स्वयं को पुलिस अधिकारी बताने वाले व्यक्ति होने ने फरियादी को उसके विरुद्ध सख्खु दर्ज होने की बात कही। आरोपियों ने आध्यात्म काई एवं पैक काई संबंधी जानकारी भी प्राप्त की। अलग दिना आरोपियों ने काल को कथितरूप से रूप से ब्रह्म विद्या में ट्रांसफर करने का नाटक किया। ब्रह्मसंपे वीडियो कॉल के माध्यम से

कोसमी गांव के प्रभावित परिवारों को मुआवजा के साथ पुनर्वास किया जाए : कांग्रेस



कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री से मांगा जवाब, निष्पक्ष जांच की मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र के कोसमी गांव में वन विभाग की कार्रवाई से मुख्यमंत्री परिवारों के प्रभावित होने के मामले में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से जवाब मांगा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने, प्रभावित परिवारों को राहत देने और यदि कार्रवाई में नियमित का उल्लंघन पाया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और प्रशासन सरकार के अधीन काम करता है। ऐसे में कोसमी के मामले में सरकार को अपनी जवाबदेही स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वी

मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले को उठाया है। अब मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि गांव में वन विभाग की कार्रवाई किसे आदेशों के तहत की गई और क्या प्रभावित परिवारों के अधिकारों एवं कानूनी दावों की जांच की गई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित परिवारों के आवास, आजीविका और भविष्य से जुड़ा है। सरकार को पटना की निष्पक्ष जांच कारकम नुकसान का आकलन करना चाहिए। साथ ही, पात्र परिवारों को निमानुसार मुआवजा, राहत और सुरक्षित पुनर्वास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच में किसी अधिकारी की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने वनाधिकार कानून के तहत आदिवासी परिवारों के दावों की स्थिति पर भी सरकार से जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने पूछा कि कितने दावे लॉबत हैं और पात्र परिवारों को उनके अधिकार दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जौतु पटवारी ने पन्ना जिले में केम-बेतवा लॉबत प्रयोजन से प्रभावित परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया।

वन्य प्राणियों के नैसर्गिक जीवन निहारने एक बार कान्हा जरूर आएँ : मुख्यमंत्री डॉ.यादव

मुख्यमंत्री ने कहा कान्हा पार्क देश का नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नेशनल पार्क



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कान्हा नेशनल पार्क हमारे देश का नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सघन वनों से आच्छादित कान्हा नेशनल पार्क मुख्यतः बाघ, चीता, लकड़बग्घा, हाथी एवं अन्य कई वन्य जीवों से समृद्ध है। उन्होंने सभी वन्य जीव प्रेमियों, पर्यटकों और नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वन्य प्राणियों के साहचर्यपूर्ण नैसर्गिक जीवन को निहारने के लिए हम से कम एक बार कान्हा नेशनल पार्क जरूर आएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की धर्ती पर हमारे समृद्ध वनों में सभी प्रकार की जीवी जंतुओं के लिए अपने प्राकृतिक आवास में स्वच्छ विचरण करने की स्वतंत्रता है। प्रदेश में बारहसिंगा को भी पुनर्जीवन मिला है। यह वन्य जीव धर्ती पर

धीरे-धीरे विलुप्त होता जा रहा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में श्योपुर जिले के वन नेशनल पार्क में हमारा चीता पुनर्बसाव प्रोजेक्ट बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव सोमवार को मंडला जिले के कान्हा किसली में स्थानीय मीडिया

प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व सरमा और उनकी सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश में जंगली भैंसों (वाइल्ड बफेलो) के पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ की है। रविवार को ही यहां 6 मादा और 2 नर जंगली भैंसों को उनके

प्राकृतिक आवास में विभुक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि प्रदेश के वनों में टाइगर, चीता, लेपर्ड, मगर, घड़ियाल और गिल्लों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे वन्य जीव मध्यप्रदेश का गौरव पर्यटन क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार वन, वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन प्रयासों से प्रदेश की जैव विविधता को सुरक्षित रखने के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे प्रयास हमारी प्राकृतिक धरोहर को और समृद्ध बना रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने प्रदेश की इस समृद्ध वन्यजीव विरासत के संरक्षण में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई दी।

भोपाल के ओल्ड सेक्टोरिएट से एक महीने के अंदर शिफ्ट होंगे सभी दफ्तर

भोपाल कमिशनर ने मीटिंग ली, 217.96 करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट बना

भोपाल। भोपाल के कोर्टोफिजा स्थित ओर
सेलेक्टोरेट में नया प्रशासनिक कारिडोर बनेगा। जिस
कारिडोर, कमिश्नर और आईजी कार्यालय को
हसमें कई विभाग है। जिसकी शिफ्टिंग शुरू हो गई
लेकिन अब भी कई विभागों ने दफ्तर खाली नहीं कि
है। इसे लेकर कमिश्नर कर्मीवी शर्मा ने अधिकांश
को एक महीने की टाइम लीमिट दी है। हर साल
विभागों को अपने ऑफिस शिफ्ट करना ही पड़े
इधर, फंडा जनपद पंचायत को भी अन्य जगह शिफ्ट
करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कमिश्नर शर्मा
सोमवार को बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश ज
करके। बता दें कि हाउसिंग बोर्ड ने मौजूदा सेलेक्टो
रेट में ही नू कं पोजिज एडमिनिस्ट्रेशन हब
निर्माण का आधिकारिक टेंडर जारी किया है। साथ
साथ वारणीय अडचनों में फंसा प्रोफेसर कालोनी वा
पुराना प्रस्ताव भी समाप्त हो गया। अब ओ
सेलेक्टोरेट परिसर ही भोपाल का नया प्रशासनि
क कारिडोर बनेगा, जहां सेलेक्टोरेट, कमिश्नर और आई
जी कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे।
निर्माण के बदले चर्चित डेवलपर को प

सिंचावार्थ परिसर में 3.36 हेक्टेयर जमीन कसईर में लैंड पार्सल (सीएलपी) के रूप में मालिकाना हक के साथ दी जाएगी। इस जमीन का मिसल लैंड यूज रखा गया है, यानी यहां रेसीडेंशियल और कमर्शियल हाईराइज प्रोजेक्ट विकसित किए जा सकेंगे। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 217.96 करोड़ रुपए है, जबकि बदले में दी जाने वाली जमीन की कीमत 256.92 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह पूरा मॉडल राज्य सरकार की टी-डिसेंटीफिकेशन नीति के तहत लागू किया जा रहा है, ताकि सरकारी खजाने पर सख्त वित्तीय बोझ न पड़े। कमिश्नर कर्मवीर शर्मा ने एफएमहीने के अंदर दफ्तर खाली करने को कहा है। साथ ही भोपाल जिले के लॉबिंग प्रकरणों को संख्या अधिक होने से उन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। संभागयुक्त शर्मा ने लॉबिंग विभागियों जांच के प्रकरणों और गुगल शीट पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण संबंधी निर्देश दिए। सीहोर जिले में गुगल शीट पर प्राप्त शिकायतों की संख्या अधिक पाई गई संभागयुक्त ने निर्देश दिए कि न्यायालयीन प्रकरणों में समय से जबाबदावा प्रस्तुत करना तथा दिए गए निर्णयों पर लंबित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए छात्रवृत्ति के लॉबिंग प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

भोपाल में ट्रेन की चपेट में आने से
आर्मी के रिटायर्ड हवलदार की मौत

भोपाल। राजधानी भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से सेना के सेवानिवृत्त हवलदार की मौत हो गई। वे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान प्रेम नगर, नागियलखेड़ा निवासी सुरेश सिंह कन्नौड़ी (57) पुत्र भवानी सिंह कन्नौड़ी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह वे रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी ट्रेन की चपेट में आ गए। गंभीर हादसे में उनकी मौत हो गई। सुरेश सिंह सेना में हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका वेतन हरीश भी सेना में नायक के पद पर तैनात है। दोपहर के समय पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। गौतम नगर पुलिस ने मामले में मर्ग कामम किया है। शुरुआती जांच में हादसा रेलवे ट्रैक पार करते समय होने की बात सामने आई है। परिजनों ने भी मौत को लेकर किसी तरह का संदेह ज़ाहिर नहीं किया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

नशीले कफ सिरप का सप्लायर

पकड़ाया, देहरादून से किया गिरफ्तार

भोपाल। नशीले कफ सिरप की अद्वैध सप्लाई के मामले में फरार आरोपी अभिषेक निगम को देहरादून से गिरफ्तार किया है। आरोपी 30 मई 2026 को भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र में पटेल सिटी में पकड़ी गई नशीले कफ सिरप की फैक्ट्री के मामले में फरार था। उस पर 20 हजार का इनाम घोषित था। एसटीएफ उसे ट्रांजिट वार्ड पर मध्यप्रदेश लेकर आई है। फिलहाल पुलिस रिमांड पर उससे पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ के मुताबिक, 30 मई को पटेल सिटी, गांधीनगर स्थित फैक्ट्री पर कार्रवाई के दौरान कोडीनयुक्त कफ सिरप की 74,104 बोतलें बरामद की गई थीं। इनमें ऑर्नक्स और ऑफकफ ब्रांड के सिरप शामिल थे। जांच में सामने आया कि अभिषेक निगम कथित तौर पर राहुल कुशवाहा और सागर निवासी सीटी जैन के साथ भित्तिरुद्वार निरपेक्ष को नशे के लिए अवैध सप्लाई करता था। आरोपी रीवा के कटरा तलैया का रहने वाला है। एसटीएफ की कार्रवाई के बाद वह रीवा से फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ के उप पुलिस महानिरीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने 20 हजार का इनाम घोषित किया था। विशेष एसी में 7 अक्टूबर को उसे देहरादून से गिरफ्तार किया

राज्यपाल मंगुभाई पटेल 15 व 16

अक्टूबर को ग्वालिंयर प्रवास पर

भाषाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल 15 अक्टूबर को ग्वालियर में दो दिवसीय प्रवास पर जाएंगे। ग्वालियर प्रवास के दौरान राज्यपाल पटेल राज्याध्यक्ष विजयराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय एवं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों में शामिल होंगे। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राज्यपाल मंगुभाई पटेल 15 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे वायु मार्ग से राजमठा विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल महाराजपुरा पहुँचेंगे। यहाँ से व्हीआईपी सर्किट हाउस मुरार जायेंगे। राज्यपाल पटेल इस दिन अपराह्न 3.15 बजे कृषि महाविद्यालय में सेंट्रल प्रोसेसिंग लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अपराह्न 3.45 बजे राजमठा विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में पहुँचकर विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के पश्चात राज्यपाल व्हीआईपी सर्किट हाउस मुरार पहुँचकर विश्राम करेंगे। राज्यपाल पटेल 16 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे।

अधिकारियों को छात्रावासों का

नियमित निरीक्षण करने के निर्देश

भोपाल। भोपाल एडीएम सुमित पांडे ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों (एडीएम) को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए मेस को सुचारु व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एडीएम पांडे सोमवार को समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में एडीएम प्रकाश नायक, एडीएम महेंद्र सिंह कवचे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, जनसमस्याओं के निराकरण और लॉबित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा की गई। पांडे ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की विभागावार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि शासकीयों के निराकरण में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। शहर के विकास और शासकीय परिसरों के सुव्यवस्थित उपयोग के लिए पुनर्जन्तवीकरण (रोडोसिफिकेशन) कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई।

